राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 31 अंक : 5

सितम्बर–अक्तूबर 2008

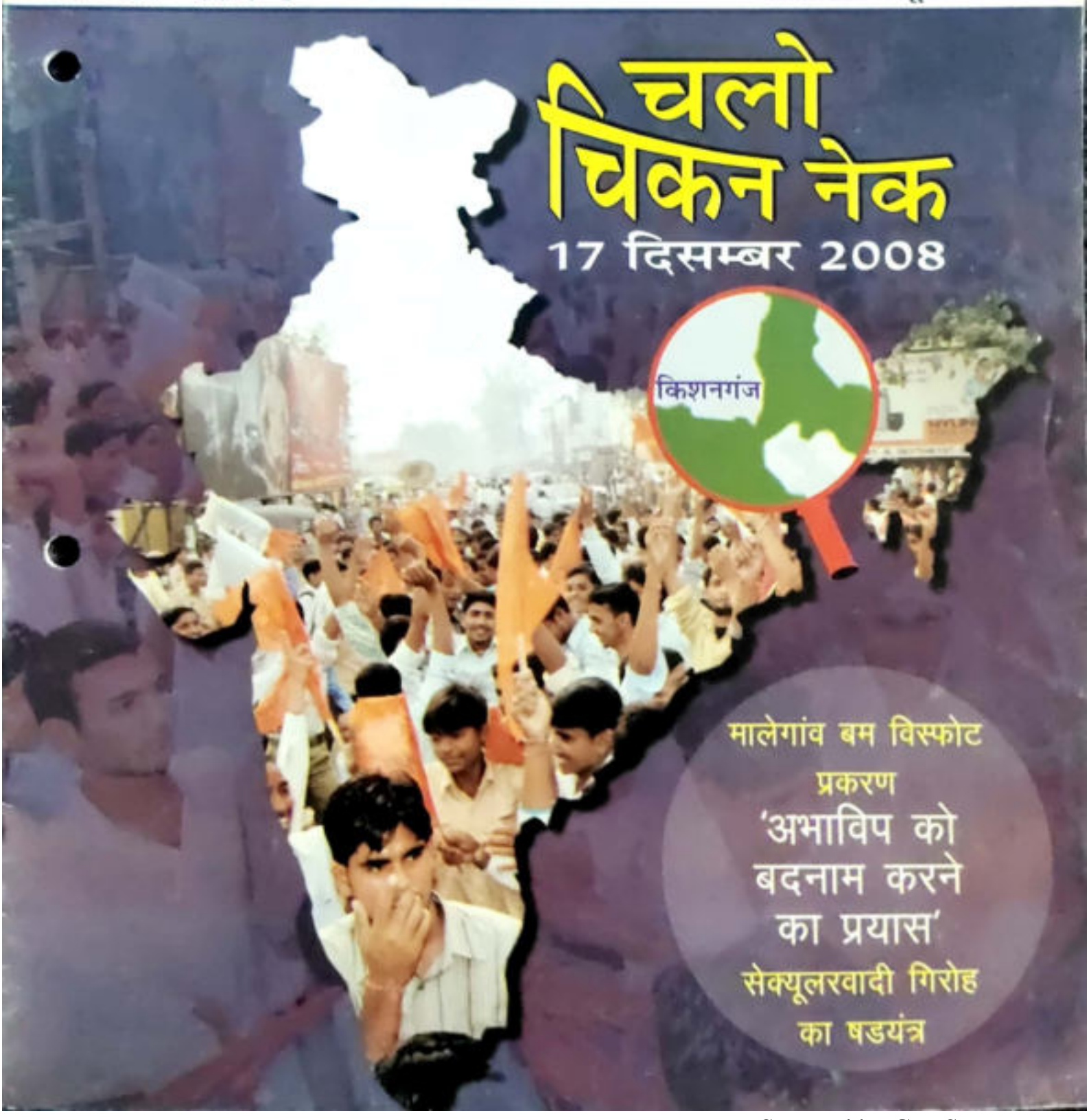

मालेगांव बम विस्फोट प्रकरण

'अभाविप को बदनाम करने का प्रयास'

सेक्यूलरवादी गिरोह का षडयंत्र

बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आन्दोलन

पटना में आयोजित अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन के उद्घाटन करते डॉ0 सुब्रमण्यम स्वामी

Karnataka Home Minister Dr V S Acharya inaugurating seminar at Kozhikkode, Kerala

विशाल रैली – जयपुर

छात्र नेता सम्मेलन – बुलन्दशहर

छात्र नेता सम्मेलन – मुरादाबाद

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
वर्ष : 31 अंक : 5 • सितम्बर–अक्तूबर 2008

संरक्षक
अतुल कोठारी
संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल
प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा
संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

फोन : 011 - 23093238, 27662477
E-mail : chhathrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

मूल्य : एक प्रति रुपए 10/–

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

6 दिसम्बर
डॉ. आंबेडकर पुण्यतिथि
सामाजिक समता दिवस

विषय सूची

7 मालेगांव बम विस्फोट प्रकरण

10 चलो चिकन नेक

15 जामिया एनकाउंटर और मुस्लिम पहचान

18 **Professional Education Under Political Pressure**

21 कंधमाल प्रकरण और मीडिया का द्वंद

25 **Crusade For Survival**

मुलाकात

श्री.श्रीनिवास – राष्ट्रीय सचिव अभाविप.....19

परिचर्चा

परमाणु करार और भारत.....27

परिषद् गतिविधियां.....28

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक, एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

एस.सी./एस.टी. छात्रावासों की स्थिति

सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों की स्थिती पर सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।

अ.भा. विद्यार्थी परिषद् ने समूचे देश भर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों का वर्ष 2006–07 में व्यापक सर्वे किया जिस सर्वे में देशभर के सभी प्रान्तों के 240 जिलों के 1130 छात्रावासों में सर्वे किया । इस सर्वेक्षण के दौरान छात्रावासों में कई तथ्य कल्पना से परे उजागर हुए । जिसमें छात्रावासों में आवश्यक क्षमता, उपलब्ध क्षमता व प्रत्यक्ष प्रवेश का तालमेल नहीं दिखा । शौचालय, स्नानघर की कमी एवम् बदतर रख रखाव भोजन व्यवस्था की व्यापक खामियां व भोजन की गुणवता की भारी कमी, महिला छात्रावासों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का व्यापक अभाव, आवश्यक बिजली एवं पानी की अनुपलब्धता तथा छात्रावास अधिक्षकों की अनुपस्थिति, अरूचि एवं कई छात्रावासों का किराये के भवनों में होना पाया गया।

इन सब गंभीर अनियमितताओं के सर्वेक्षण के दौरान उजागर होने के कारण अ.भा. विद्यार्थी परिषद् ने सारे देश में राज्य सरकारों एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन एवं छात्र प्रदर्शन कर अवगत कराया लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आने के कारण विद्यार्थी परिषद् ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी कि –

1. केन्द्र एवं राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाये कि भारतीय संविधान की धारा 46 के अन्तर्गत एस.सी./एस.टी. एवं कमजोर वर्ग को दिये गये अधिकारों की रक्षा की जाये।
2. एक कमेटी का गठन किया जाये जो एस.सी./एस.टी. छात्रावासों का सर्वे करते हुए छात्रावासों की दुरावस्था के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में माननीय न्यायालय को अवगत कराये।
3. प्रत्येक राज्य से एस.सी./एस.टी. छात्रावासों की स्थिति एवं रिपोर्ट मांगी जाये।
4. एस.सी./एस.टी. छात्रावासों एवं विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आवंटित राशि का उपयोग ठीक से सुनिश्चित किया जाये।
5. एस.सी./एस.टी. छात्रावासों के रखरखाव में अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।
6. एस.सी./एस.टी. बालिका छात्रावासों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाये जायें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन सारे तथ्यों से अवगत होकर सुनवाई करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। ■

आतंकवाद का सांप्रदायिकरण बंद करो

कांग्रेसनीत संप्रग सरकार देश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में किल रही है। हाल ही में बेंगलुरु, अहमदाबाद, असम और दिल्ली में हुए बम धमाकों से लोग सहमे हुए हैं। कांग्रेस न सिर्फ आतंकवाद की जननी है बल्कि उसके राज में यह फल-फूल भी रहा है। इसी पार्टी ने पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को प्रश्रय देने के साथ कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। नक्सलवाद भी कांग्रेस की गलत नीतियों की देन है।

संप्रग सरकार आंतकवाद का सांप्रदायीकरण कर रही है। मालेगांव कांड को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। कई अहम साधु-संतों और उनके आश्रमों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना को भी घसीटने की साजिश हो रही है। यह सब सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश कर उनके वोट हासिल करने का प्रयास है। इतना ही नहीं देश में घुसपैठ कर अवैध रुप से रह रहे डेढ़ करोड़ से अधिक बांग्लादेशियों को यहाँ से निकालने की माँग पर भी संप्रग सरकार न सिर्फ मौन है बल्कि उनके मतदाता पत्र बनाकर उन्हें देश की राजनीति में हिस्सेदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह कितना शर्मनाक एवं दुखद है कि साहसी योद्धा दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा की मौत को भी छद्मपंथनिरपेक्ष नेताओं ने फर्जी बताने में शर्म नहीं किया। हाल में दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के बाद जामिया नगर के बटाला हाउस में हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादियों के मारे जाने की घटना को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा फर्जी मुठभेड़ बताया गया। इन राजनीतिक दलों की सोच इस कदर घटिया हो गयी है कि वह देशभक्त सिपाहियों की मौत को फर्जी मौत और आतंकवादियों की मौत को शहादत बताने लगे हैं।

आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के प्रयासों के तहत कांग्रेसनीत केंद्र सरकार मालेगांव विस्फोट मामले में हिंदू नेताओं को फंसा रही है। महाराष्ट्र के आतंकवाद-निरोधक दस्ते (एटीएस) ने हिंदू नेताओं के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन केंद्र सरकार साध्वी प्रज्ञा को तरह-तरह की यातनाएं दे रही है। केंद्र एवं महाराष्ट्र सरकार साध्वी प्रज्ञा का चार बार नारको टेस्ट और चार बार ब्रेन मैपिंग करा चुकी है। इतने टेस्ट बड़े से बड़े आतंकवादी के नहीं किए गए हैं। वहीं क्या कारण है कि संसद पर हुए हमले में शामिल अफजल गुरु जैसे आतंकी को उच्चतम न्यायालय द्वारा फाँसी की सजा सुनाए जाने पर अब तक उसे फाँसी पर नहीं लटकाया गया। संप्रग सरकार के समय में पिछले पांच सालों में देश में जितने भी बम विस्फोटों की घटना हुई हैं उसमें से एक भी घटना में किसी भी दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई है लेकिन साध्वी प्रज्ञा के मामले में पर्याप्त सबूत जुटाने में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है जो संदेह पैदा करती है।

विद्यार्थी परिषद् आतंकवादी घटनाओं की जांच के खिलाफ नहीं है और न ही दोषियों को बचाने की हिमायत करती है। लेकिन सभी कार्रवाई पुख्ता सबूत के आधार पर ही होनी चाहिए। केंद्र सरकार बेवजह राष्ट्रवादी संगठनों को परेशान करने से बाज आए अन्यथा उसकी यह मुहिम उसे बहुत महंगी पड़ेगी। ■

घुसपैठ के खिलाफ बांग्लादेश दूतावास पर विशाल प्रदर्शन

कोलकत्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् पश्चिम बंगाल प्रदेश इकाई द्वारा 10 सितम्बर 2008 को बांग्लादेशी घुसपैठ तथा आंतकवाद के खिलाफ कोलकत्ता में अवस्थित बांग्लादेश दूतावास पर विशाल प्रदर्शन किया गया हजारों की संख्या में छात्र ऐतिहासिक 'कॉलेज स्कवायर' में एकत्रित हुआ एवं एक सभा का आयोजन किया। सभा को मुख्य रूप से घुसपैठ विरोधी आंदोलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक सुनील बंसल, पश्चिम बंगाल के प्रदेश मंत्री बिलेश्वर सिंह आदि ने संबोधित किया।

सभा के बाद छात्रों ने कॉलेज स्क्वायर से लेकर पार्क सर्कस स्थित बांग्लादेश उच्चायुक्त कार्यालय तक एक विशाल जुलूस निकाला तथा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश के 23 जिलों (183 स्थानों) से 4064 छात्रों ने भाग लिया जिसमें 78 छात्राएँ भी थी। बैनर एवं तख्तियाँ लेकर बांग्लादेश हाईकमीशन की ओर मार्च कर रहे हजारों छात्रों को पुलिस ने ब्रेबर्न कॉलेज के पास रोक दिया। बैरिकोटिंग के कारण छात्रों एवं पुलिस के बीच धक्का–मुक्की हुई एवं रैफ जवानों द्वारा लाठी चार्ज किया गया जिसमें कई छात्र घायल हो गये। प्रदर्शन के दौरान छात्र पुरी तरह अक्रामक मुद्रा में भारत माता की जय, वन्दे मातरम, बांग्लादेश हाय–हाय, बांग्लादेशी घुसपैठियों वापस जाओ आदि नारे लगा रहे थे।

Supreme Court Seeks Govt. Response On Condition Of Hostels For Dalits

The Supreme Court sought a response from the Centre, state governments and UTs on a plea alleging that they have failed to provide basic facilities in hostels meant for Scheduled Caste and Scheduled Tribes students despite huge allocation of funds.

The PIL filed by Akhil Bharatiya Vidhyarti Parishad (ABVP), alleged that hostels constructed and run by the Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs to facilitate education of SCs and STs lack facilities like toilets, water and power supply.

A Bench headed by Chief Justice K G Balakrishnan agreed to hear the petition after advocate Bhupender Yadav said a detailed research done by the ABVP found that despite huge allocation of grants under various schemes such hostels, for both girls and boys, are in a bad state.

The ABVP said some of these hostels are being utilised for other purposes. A girls' hostel in Varanasi in Uttar Pradesh was being used as a Beggars' Home and a hostel constructed at the cost of Rs 31.26 lakhs having capacity of 140 students at Malda in West Bengal was being used for accommodation of police personnel.

The survey disclosed that at one such hostel in Saharanpur in Uttar Pradesh, there were just two toilets to cater to 100, the PIL said.

Under the scheme, 50 per cent central assistance is given for construction of hostels and remaining 50 per cent is born by the concerned state government. In the case of Central government institutions 100 per cent assistance is given by the central government.

The survey was carried out at 985 such hostels of 208 districts of 14 states.

अभाविप को बदनाम करने का प्रयास

सेक्यूलरवादी गिरोह का षडयंत्र

सुनील आंबेकर
राष्ट्रीय संगठनमंत्री, अभाविप

गत 23 अक्तूबर 2008 को इंडियन एक्सप्रेस सहित कुछ समाचार पत्रों ने एक समाचार छापा जिसमें मालेगांव विस्फोट (29 सितंबर, 2008) में अभाविप. का सहभाग होने का दावा किया गया। 23 सितंबर को दोपहर के पूर्व ही लगभग हमारे सभी तेज तर्रार चैनलों में होड मच गयी व 'मालेगांव विस्फोट मे अभाविप का हाथ' अभाविप का आतंकी चेहरा' जैसे समाचार Breaking News के रूप में चमकने लगे।

सच को समझे बिना उसे तोड़मरोड़कर पेश करते हुए विद्यार्थी परिशद् को बदनाम करने का कम प्रारंभ हो गया। हालांकि उसी दिन तुरन्त कई चैनलों से संपर्क करते हुए या उनके द्वारा संपर्क होने पर हमारी भूमिका को हमने स्पश्ट किया एवं तुरंत में श्री सुनील बंसल ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। दूसरे दिन मुंबई में राश्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.मिलिंद मराठे द्वारा भी पत्रकार वार्ता हुयी। फिर भी कुछ बाते विस्तार से ध्यान में लाने हेतु यह जानकारी भेज रहा हूँ।

मालेगांव विस्फोट या ऐसी किसी भी हिंसक गतिविधियों से न तो परिषद् का कोई संबंध है न ही परिषद् ऐसे हिंसक मार्ग पर विश्वास करती है। विद्यार्थी परिषद् सार्वजनिक जीवन में एक प्रतिष्ठित संगठन है एवं लोकतांत्रिक तरीकों से सतत 60 वर्षो से कार्यरत है। परिषद् आतंकवाद तथा नक्सलवाद जैसी हिंसक गतिविधियों के विरोध में लोकजागरण एवं आंदोलनों के माध्यम से निरंतर सक्रिय है। परिषद् के कई कार्यकर्ता भी ऐसे आंदोलन के कारण आतंकवादियों व नक्सलियों द्वारा मारे गये, ऐसे शहीदों की भी एक लंबी श्रृखंला है। तुष्टीकरण व वोट बैंक की राजनीति के स्वार्थवश तथा तथाकथित सेक्युलरवाद के नाम पर आतंकी एवं नक्सलियों का समर्थन करने वाले राजनैतिक दल, मानवाधिकार सामाजिक कार्यकर्ता एवं मीडिया के कुछ लोगों के दोगलेपन को भी परिषद् ने बार-बार उजागर किया है।

आज जब पूरे देश में मुस्लिम आतंकवाद एवं नक्सलवाद सतत पनप रहा है। तथा उसे रोकने में उपरोक्त सभी सेक्युलर ताकतें असफल हो रही हैं। इसलिये उसे छुपाने के लिऐ हिंदू आतंकवाद का नया झुठा-मूठा भूत खड़ा करते हुए परिषद् जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन को बदनाम करने का षडयंत्र चलाया गया है। परिषद् जैसे राष्ट्रवादी संगठन और हिंदुत्व की शक्तियों को कमजोर करने की यह सोची-समझी साजिश है। संक्षेप में कहें तो यह भी एक प्रकार से वोट बैंक के राजनैतिक स्वार्थ में अंधो होकर आतंकवादियों के प्रति जनता के आक्रोश को शांत करने का रवैया अपनाते हुए देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का घिलौना खेल है।

यह उचित होगा कि केंद्र की यूपीए (UPA) सरकार

के कांग्रेस सहित श्री मुलायमसिंह, श्री लालू प्रसाद यादव,तथा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद व घुसपैठ जैसी घटनाओं का हमेशा समर्थन करने वाले अन्य दल मुस्लिम आतंकवाद को रोकने हेतु कडा रूख अपनाते हुए ठोस कारवाई करें।

सुश्री वृंदा करात जैसे कम्युनिष्ट मानवाधिकार का सहारा लेकर सर्वाधिक हिंसक नक्सलियो का समर्थन तथा मुस्लिम आतंकवादियों की कई घटनाओं पर चुप्पी साधते हैं, वहीं नंदीग्राम व सिंगूर में गरीब लोगों पर अनंत अत्याचार करते है तो आज उनका मालेगाव विस्फोट में हिंदुवादी संगठनो पर टिप्पणी करना उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है।

जहाँ तक परिषद् का सवाल है, वह राष्ट्रविरोधी ताकतों के विरूद्ध अपनी लड़ाई जारी रखेगी। परिषद् ने कश्मीर का आतंकवाद हो या देशभर में हो रही अन्य ऐसी घटनाएँ हो उसका कड़ा विरोध किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का भयंकर चेहरा हो या हमारे सेक्युलर दलों के द्वारा देश को भ्रमित करने की नीतियां हो, परिषद् लगातार जनता के सामने उजागर कर रही है।

मालेगांव विस्फोट के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गयी साध्वी पूर्णचेतना गिरी (पूर्वाश्रमी की सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर) अपने छात्र जीवन में परिषद् की कार्यकर्ता रही है। तथा निष्ठावान एवं सक्रिय होने के कारण उन्होंने 1997 तक परिषद् के विभिन्न दायित्वों को निभाया है। उसके पश्चात वह आध्यात्मिक साधना की ओर मुडी व कुछ वर्ष पूर्व सन्यास लेकर साध्वी बन गयी। अर्थात 1997 के पश्चात उनका परिषद् की नियमित गतिविधियों से संपर्क नहीं रह पाया।

पूर्व में परिषद् कार्यकर्ता रहने के नाते हमें विश्वास है कि वह बम विस्फोट जैसी गतिविधियों मे कभी भी लिप्त नहीं हो सकती तथा हिंदुत्ववादियों को बदनाम करने के उद्देश्य से उन्हें षडयंत्र के तहत मालेगांव विस्फोट मामले में फँसाया गया है। फिर भी पुलिस व **ATS** उसकी जॉच करे यह तो हमें मंजूर है, परंतु जॉच के नाम पर सेक्युलरवादी दल तुष्टीकरण की राजनीति करें, पुलिस उनके इशारे पर काम करें, मिडिया के कुछ लोग हिंदुत्ववादी शक्तियों को बदनाम करें तथा अभाविप जैसे राष्ट्रवादी संगठन को घसीटे यह सहन नहीं किया जायेगा।

इसलिए परिशद् चाहती है कि:–

- केंद्र सरकार तुरंत सुश्री प्रज्ञा सिंह को वैधानिक कानूनी सहायता प्रदान करे।
- पुलिस अपने दायरे में रहते हुए अनावश्यक रूप से जॉच के मुद्दे मीडिया में उछालना बंद करे व एवं राजनैतिक नेताओं के इशारो पर लोगों को परेशान करने से बचे।
- मीडिया बिना ठोस आधार के परिषद् को बदनाम करना बंद करना बंद करें वरना कई कानूनी विवादों से जूझने के लिये तैयार रहें।
- जनता व विशेषकर छात्र–युवा इस षडयंत्र को समझते हुए राष्ट्रविरोधी एवं आतंकी शक्तियों तथा उनकी समर्थक सेक्युलर ताकतों के विरोध मे अपनी आवाज बुलंद करें।

कुछ संदर्भ:–

1. दि. 9 अगस्त, 2008 को **IBN** एवं लोकमत तथा अन्य मे कई समाचार माध्यमों ने प्रकाशित किया कि अभाविप नक्सलियों को आर्थिक सहयोग करती है।

   जेल मे बंद एक नक्सली अरूण परेरा ने अपनी नारको टेस्ट मे उपरोक्त बातें कही, ऐसा दावा उन समाचार में किया गया था। अभाविप को बदनाम करने का प्रयास चला। दिनांक 6 अक्तूबर, 2008 को रश्मि शुक्ला (पुलिस उप महानिरीक्षक, महाराष्ट्र) ने एक पत्र द्वारा स्पष्ट किया कि अरूण परेरा ने अपनी नारको टेस्ट में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया। लेकिन अपनी इस गलती को सुधारने का कष्ट अपवाद स्वरूप ही किसी समाचार माध्यम ने किया।

2. जामिया नगर – दिल्ली (29 सितंबर, 2008)

   आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ मे बहादुर पुलिस अधिकारी श्री मोहनचंद शर्मा शहीद हुए। एक आतंकी मारा गया व एक पकड़ा गया। बाद में और एक छात्र जामियामिलिया विश्वविद्यालय से पकड़ा गया। लेकिन हमारे सेक्युलरवादी दलों की राजनीति तुरन्त प्रारंभ हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अमरसिंह ने तो इस मुठभेड को फर्जी बताकर इसकी जॉच की मॉग की तथा जामिया के छात्रों के पक्ष में मैदान में उतरे। उनको देखकर जामिया विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मशरूल हुसैन ने तो हद कर दी, उन्होने उन छात्रों को विश्वविद्यालय की तरफ से तुरन्त कानूनी सहायता देने की घोषणा की तथा सभी शिक्षकों की ओर से एक दिन का वेतन भी इस कार्य हेतु रख लिया एवं उनके समर्थन में एक शांती मार्च भी आयोजित किया। यह सीधे–सीधे आतंकवादीयों के समर्थन की मिसाल है।

3 अफजल (संसद पर हमले का दोषी) की फॉसी का

विरोध करने में कांग्रेस के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद से लेकर सभी ऐसे सेक्युलरवादी मैदान में उतरे व अभी तक अफज़ल को फाँसी नहीं हो पायी है।

4. कोई भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो उनको समर्थन करने वाले कुछ राजनैतिक दल, मीडिया के कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी, सेक्युलरवादी फौजें मिलकर मानवाधिकार, अल्पसंख्यक सुरक्षा आदि का नाम लेकर उनके समर्थन में खड़े हो जाते है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि, यही फौज मुस्लिम आतंकवाद के प्रति लोगो की आक्रमकता को कम करने हेतु 'हिंदू आतंकवाद' की काल्पनिक कहानी गढ़ना चाहती है। जब कि सभी जानते हैं कि मदरसों, कुछ धार्मिक नेताओं एवं मस्जिदो के माध्यम से भारत विरोधी आतंक को प्रश्रय तथा प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, यह कहकर मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद, मदरसे तथा मौलवियों को इन दायित्वों से अलग कर के दिखाना चाहते है। ताकि उनकी, तुष्टीकरण की देश व समाज विरोधी नितियों के संदर्भ में सम्पूर्ण समाज भ्रमित रहे। दूसरी तरफ 'हिंदू आतंकवाद', सांप्रदायिक आदि विशेषण लगाकर संघ व उससे संबंधित विविध संगठनों एवं अन्य सभी हिंदूत्ववादी शक्तियों को कठघरे में खड़ा करते हुए उन्हे कमजोर करना चाहते हैं। ताकि उनकी यह घातक राजनीति मुक्त रूप से चलती रहे।

मालेगाव बंम विस्फोट प्रकरण: हिंदूत्व भाक्तियों को बदनाम करने का षडयंत्र

कुछ अन्य बातें:–

1. **CNN-IBN** जैसे कुछ चैनलों तथा **Indian Express** के पास पुलिस जांच की दिशा के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही कैसे उपलब्ध थी ? क्या इस पूरे षडयंत्र में उन्हे भी शामिल किया गया था ?
2. साध्वी प्रज्ञासिंह को 14 अक्तूबर को मुंबई **ATS** ने पकड़कर अपने मुख्यालय रखा परंतु 24 अक्तूबर को कोर्ट के सामने पेशी हुयी। इस अवैध कार्रवाई पर मानवाधिकार आयोग आज तक चुप क्यों है ?
3. क्या विस्फोट करने वाला अपने स्वयं के वाहन को विस्फोट करने के लिए उपयोग करने की मुर्खता करेगा? पुलिस का दावा है साध्वी प्रज्ञासिंह की बाईक में ही मालेगाव में विस्फोट हुआ और इसलिऐ उन्हे पकड़ा गया है।
4. मुबई **ATS** को साध्वी प्रज्ञा की ब्रेन मैपिंग व पोलीग्राफ टैस्ट मे जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि योग तथा ध्यान में कुशल होने के कारण, उन्होंने अपने मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण परीक्षण का निष्कर्ष सामान्य रहा। पुलिस जॉच पूरी तरह करे, परन्तु ऐसे दावों से तो उसे बचना चाहिए। पुलिस द्वारा दोबारा ब्रेन मैपिंग व पोलीग्राफ टेस्ट करने की बात करना ये संदेह पैदा करता है कि पुलिस द्वारा अपेक्षित बात नहीं कहने तक टेस्ट जारी रहेगा।
5. कुछ समाचार माध्यम जैसे एन.डी.टी.वी., इंडिया टी.वी, सी.एन.एन.–आई.बी.एन. व इंडियन एक्सप्रेस आदि लोगों ने जिस तरह से आतंकवाद जैसे गंभीर विषय को राजनैतिक व सनसनीखेज बनाकर बेहद हल्के ढंग से प्रस्तुत किया है। इसका विरोध जरूरी है। एक सेना अधिकारी के इस मामले में गिरफतार होने पर इन्होने पूरी सेना को ही नकारात्मक चर्चा में घसीटने का प्रयास किया हैं। ज्यो सेना आतंकवाद के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर लड रही हो, उसका मनोबल तोडने का हर प्रयास शर्मनाक हैं। जनता को इन्हे यह बता देना चाहिए वे इन आधारहीन बातों के प्रचार को बंद करें अन्यथा ऐसे चैनलों का बहिष्कार होगा। साथ ही स्थान–स्थान पर कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी।

अगर दुर्भाग्य से कुछ हिंदू युवकों का आतंकवादी गतिविधियों मे सहभाग पाया जाता है तो भी उसके लिए हिन्दुत्व जागरण के लिए सक्रिय तथा मुस्लिम आंतकवाद का विरोध करने वाले संघ या उससे संबंधित अन्य संगठनो को दोष देना उचित नहीं होगा। मूलतः सौम्य एवं सहनशील स्वभाव के हिंदू युवाओ को अगर गुस्सा आता है तो उसका मुख्य कारण वर्तमान केंद्र सरकार व कॉंग्रेस सहित कई सैक्युलर दलों की मुस्लिम आतंकवादियों के प्रति ढीली–ढाली नीति है।

देश में मुस्लिम आतंकवादी लगातार देश के हर कोने में विस्फोट कर रहे है देश की सरकार एक तरफ तो उनको नियंत्रित करने में असफल है वहीं दूसरी ओर अपने राजनैतिक स्वार्थ के कारण अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की नीति जारी रखते हुए उनको बचाने में लगी है। इसलिए यह आवश्यक है कि स्वार्थ की राजनीति छोड़कर देश के हित में मुस्लिम आतंकवादियों पर लगाम कसते हुए उन पर कड़ी कारवाई करना ही इस समस्या का समाधान है। ■

चलो चिकन नेक

– सुनील बंसल –

(राष्ट्रीय संयोजक
बंगलादेशी घुसपैठ विरोधी आंदोलन समिति)

गत दो दशकों से भारत में बढ़ रही आंतकवादी घटनाओं ने देश में असुरक्षा का माहौल बढ़ा दिया है। पिछले दो वर्षों में मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी, अहमदाबाद, त्रिपुरा एवं असम में सीरियल ब्लास्टों में सैंकड़ों निर्दोष एवं बेगुनाह लोग मारे गये हैं। 1947 के देश विभाजन से लेकर 1989 में कश्मीर तक व आज भी यही मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें समय–समय पर अपना अहसास कराती रहती है। यही आंतकवादी ताकतें पाकिस्तान व बंगलादेश के इशारे पर भारत में दशहत का वातावरण बनाकर हमारी सुरक्षा एवं एकात्मता के लिए खतरा बन गई हैं।

पूर्व में पाकिस्तान की सीमा से आंतकवादी व हथियार बड़ी मात्रा में आते रहे हैं लेकिन सीमा पर सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी होने पर उसमें रोक लगती दिखाई देती है। लेकिन बंगलादेश से लगी 4096 कि.मी. की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं होने से आज बढ़ी संख्या में घुसपैठिये, प्रशिक्षित आंतकवादी, हथियार, नशीले पदार्थ भारत में लाए जा रहे हैं।

विद्यार्थी परिषद् द्वारा 2007 में बंगलादेश से लगी सीमा के सर्वे में वहां पर सुरक्षा की ढीली ढाली व्यवस्था देखकर गंभीर संकट का अनुभव होता है। लगभग 6000 घुसपैठिये रोजाना बंगलादेश की सीमा से भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। तीन करोड़ से ज्यादा घुसपैठिये भारत में फैल चुके हैं।

इन बंगलादेशी घुसपैठियों के कारण सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। छब्बीस से अधिक जिले मुस्लिम बहुल हो गये हैं और वहां पर रहने वाला हिन्दु अल्पमत में आ गया है। इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या के बल का प्रभाव वहां के सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। अल्पमत में आये वहां के हिन्दू समाज के जीवन में कई प्रश्न उपस्थित हो गये हैं। हर दिन उन पर अत्याचार होना आम बात हो गयी है। उनके सामने दो ही विकल्प हैं या तो वह इन परिस्थितियों से समझौता कर लें या वहां से पलायन कर जायें। वे स्वाभिमान के साथ अपने ही देश में अपना सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। खुले आम गाय के मांस की बिक्री होती है। शाम को वे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। माँ–बहनों की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है। इस प्रकार की दयनीय परिस्थिति में वहां के हिन्दू समाज का मनोबल बढ़ाना अति आवश्यक है ताकि वह वहां से पलायन न करें और डटकर इन आंतकवादी ताकतों से अपने पुरखों एवं पूर्वजों की जमीन व मातृभूमि की रक्षा के लिए मुकाबला करें।

सरकार, प्रशासन एवं सुरक्षातंत्र की कमजोरी के कारण घुसपैठ का बढ़ना व उस क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे उत्पन्न होना यह तो दिखाई दे रहा है लेकिन कांग्रेस, वामपंथी व अन्य दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए इन घुसपैठियों को संरक्षण देना ज्यादा चिंताजनक है। असम में उदालगुड़ी की घटना इसका ताजा उदाहरण है।

हमें बंगलादेश की मानसिकता को भी समझना होगा। आज वह बंगलादेश नहीं पूर्वी पाकिस्तान वाली मानसिकता में लौटता दिखाई दे रहा है। वह मित्र नहीं शत्रु देश की तरह व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान, चीन व विश्व के इस्लामी देशों के साथ हाथ मिलाकर भारत विरोध का झंडा उठाता रहता है। आज वह घुसपैठियों के माध्यम से भारत की भूमि पर कब्जा

करना चाहता है व आंतकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत में अलगाववादियों को सहयोग प्रदान कर रहा है।

दूख तब होता है जब हमारी सरकार व राजनैतिक दल, नेता व जनता भी बंगलादेश के गरीबी व भूखमरी के नाम पर विलाप के कारण गुमराह हो जाते हैं। हम आज तक उसकी इस्लाम के नाम पर विस्तार करने की योजना व भारत का वह हमेशा विरोध करेगा। इस नीति को हमारी सरकार, विदेश मंत्रालय, गृह, रक्षा विभाग विफल रहे हैं।

अभाविप् इस समस्या के प्रारंभकाल से ही असम व पूरे देश में सभी का ध्यान उस ओर दिलाती रही है कि यह समस्या केवल असम तक सीमित न होकर सम्पूर्ण देश को प्रभावित करेगी और आज वही होता दिखाई दे रहा है। परिषद् द्वारा 1979–83 के देशव्यापी सत्याग्रह के बाद आई.एम.डी.टी. कानून का विरोध, राष्ट्र जागरण अभियान, सीमा का सर्वे के माध्यम से बंगलादेशी घुसपैठ का मुद्दा हमेशा उठाती रही है। इसी क्रम में वर्तमान में बंगलादेश घुसपैठ विरोधी आंदोलन देश भर में चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों के हिन्दू समाज का मनोबल बढ़ाना व घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े उपाय बनाने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने हेतु देश में जन आन्दोलन खड़ा करना है।

- **बंगलादेशी घुसपैठ विरोधी आंदोलन** –राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक हुबली में इस विषय पर देशव्यापी आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया गया जिसमें महाविद्यालय से लेकर समाज तक व्यापक जागरण की योजना बनाई गई।
- **घुसपैठ विरोधी सप्ताह – (7–14 अगस्त)** के अन्तर्गत देशभर के 915 स्थान के 2135 महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों में सम्पर्क किया गया व प्रधानमंत्री के नाम पर महाविद्यालय के छात्रों द्वारा ज्ञापन भेजा गया।
- **संकल्प दिवस (14 अगस्त)** – को 653 नगर इकाईयों में सार्वजनिक स्थानों पर 11,54,434 छात्रों ने आकर घुसपैठ के विरोध में प्रभावी आन्दोलन चलाने व अपनी मातृभूमि की सुरक्षा हेतु संकल्प लिया।
- **जिला रैली,प्रदर्शन** :139 जिलों व विश्वविद्यालय में छात्रों के विशाल प्रदर्शन हुए जिसमें 1,23,220 छात्र–छात्रा सहभागी हुये। स्थानिय प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सरकार को भेजे गए।
- **सेमीनार** : बंगलादेशी घुसपैठी समस्या और इसके समाधान को लेकर देश भर में (बैंगलौर, जयपुर, मुम्बई, भोपाल, सिलीगुड़ी, दिल्ली) बुद्धिजिवी एवं सुरक्षा विशेषज्ञ के साथ इस पर गहन विचार विमर्श हुआ। बैंगलौर – 7 नवम्बर, जयपुर – 13 नवम्बर (बंगलादेशी घुसपैठ एवं सीमा प्रबंधन), मुम्बई – 16 नवम्बर, भोपाल – 6 सितम्बर, दिल्ली – 5 दिसम्बर, सिलीगुड़ी
- **देशव्यापी कॉलेज बन्द (12 नवम्बर, 2008)**–घुसपैठ के विरोध में देशव्यापी कॉलेज बन्द के आहवान को व्यापक समर्थन मिला 390 जिलों के 2732 स्थानों के 7312 महाविद्यालय व 15036 कॉलेज पूर्णरूप से बंद रहे। अधिकांशम महाविद्यालयों ने स्वत: ही समर्थन में बन्द रखा। बंद के आहवान को देखते हुए कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी परिक्षायें भी स्थगित की। तमिलनाडू में 10 दिसम्बर व महाराष्ट्र, गुजरात,विदर्भ, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में 2 दिसम्बर को कॉलेज बन्द रहेंगे।

चलो चिकन नैक – चिकन नैक उत्तर पूर्वी क्षेत्र और शेष भारत को जोड़ने वाला भू भाग है। इसकी लम्बाई 32 कि.मी. और चौड़ाई 21 से 24 कि.मी. है। बिहार व पश्चिम बंगाल राज्य के किशनगंज और उत्तरी जिले का यह हिस्सा है। नेपाल, बंगलादेश, चीन की सीमाएं चिकन नैक से लगती हैं या नजदीक हैं। पश्चिम बंगाल के दालकोला से भोलामारी तक सडक मार्ग NH 31 और उत्तरपूर्व क्षेत्र में जाने का रेलमार्ग एकमात्र जमीनी संपर्क का साधन है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत बंगलादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है।

इसी चिकन नैक क्षेत्र (किशनगंज) में आगामी 17 दिसम्बर को देश भर के 50 हजार छात्र–छात्रायें बंगलादेशी घुसपैठ के विरोध में एकत्र आयेंगे और वहां पर 5 अलग–अलग स्थानों से रैली निकालकर अन्त में सभा व प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करायेंगे। अन्त में स्थानीय जिलाधीश को अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपा जायेगा व दिल्ली में भी गृहमंत्री से एक प्रतिनिधि मण्डल मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए अपना मांग पत्र देगा।

17 दिसम्बर, 2008 – चलो चिकन नेक अभाविप की मॉगे

1. **सीमा सुरक्षा को प्रभावी बनाना आवश्यक है इस हेतु–**

क. भारत–बंगलादेश सीमा संपूर्ण सील करें।

ख. ताराबंदी अतिशीघ्र पूरी करें, तथा उसे परिणामकारक बनाने के लिए उसमें विदयुत प्रवाह छोड़ने की व्यवस्था, आधुनीक उपकरण, फ्लूड लाईटस, सर्च टॉवर्स आदि उपाय जरूरी है।

ग. सीमा सुरक्षा बलों को (बी.एस.एफ.) व्यापक अधिकार प्रदान हो। किसी भी तरह की तस्करी रोकने तथा घुसपैठ रोकने हेतु निश्चित स्पष्ट सूचना हो। जैसे घुसपैठियों पर गोली चलाना आदि।

घ. सीमावर्ती क्षेत्र में तथा प्रत्यक्ष सीमा रेखा के ऊपर स्थित सभी मस्जिदों तथा मदरसों की जांच हो। देश की सुरक्षा को देखते हुए अवैध सभी निर्माण हटायें जायें।

2. घुसपैठियों को प्राप्त संरक्षण समाप्त होना जरूरी है, इस हेतु–

क. घुसपैठियरों की पहचान करके मतदाता सूची से नाम हटाने एवं उनकी नागरिकता समाप्त करने हेतु स्वतंत्र टास्क फोर्स बनें। पहचानो, नाम हटाओ, वापस भेजो की नीति बनायें। (Detect, Delete & Deport)

ख. घुसपैठ संबंधी सभी मामलों को चलाने के लिए Fast Track Court का गठन हो सभी राज्यों में हो।

ग. घुसपैठ के विषय में तथा घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों के लिए कड़ा कानून बनें।

3. सीमा सुरक्षा में स्थानीय समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है, इस हेतु–

क. सीमावर्ती गांवों में दूरसंचार तथा यातायात की व्यवस्था अतिशीघ्र पूर्ण हो। जैसे फोन, मोबाईल सुविधा, सड़क आदि।

ख. सीमा से सटे क्षेत्र में निर्माण हुए नये गांवों की जांच हो।

ग. सीमावर्ती क्षेत्र में बसे भारतीय नागरिकों की उन्नती तथा सुरक्षा हेतु विशेष विकास योजना कार्यान्वित हो।

4. उत्तर–पूर्वी राज्यों में घुसपैठ समस्या अधिक गंभीर है, इस हेतु–

क. बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गयी वनांचल भूमि, जनजातीय क्षेत्र, सत्रों (मंदिर) की भूमी, सरकारी भूमि त्वरित मुक्त करायी जाये।

ख. भारतीय नागरिकों के प्रताड़न को रोकने हेतु सुरक्षा हे व्यापक प्रबंध हो।

ग. उत्तर–पूर्वी राज्यों में बढ़ता आतंकवादियों का जाल इस्लामी कहरपंथी गुटों पर काबू पाने हेतु खुफिया ए तथा सैन्य अधिकारों का उपयोग करें।

5. सीलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नैक) –

क. चिकन नैक क्षेत्र को त्वरित अवैध निवासी तथा निर्मा खाली कराया जाये।

ख. सुरक्षा के दृष्टि में यह क्षेत्र Special Protection Z घोषित हो।

ग. इस क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से सैन्य के हवाले करें।

Nationwide College Bandh – 12 November, 2008

Sl.No	Province	Place	Districts	College	Junior College	University
1.	Kerala	93	14	535		04
2.	Karnataka	705	30	2000	3081	13
3.	Tamilnadu	10 December				
4.	Andhra Pradesh	695	23	1800	5698	08
5.	Maharashtra	2 December				
6.	Gujarat	2 December				
7.	Vidharbha	2 December				
8.	Madhya Bharat	137	33	366	210	02
9.	Mahakoshal	64	21	180		03
10.	Chhattisgarh	2 December				
11.	Orissa	2 December				
12.	Paschim Bangal	31	23	35	41	01
13.	Asam	16	08	45	53	
14.	N. East	49	03	40	212	01
15.	Jharkhand	92	22	126	526	03
16.	Bihar	134	36	252	1862	08
17.	East. UP	51	21	74	177	04
18.	Central UP	28	18	69	210	02
19.	Western UP	210	27	478	985	04
20.	Uttaranchal	85	16	100	1500	10
21.	Rajasthan	162	38	776		07
22.	Delhi	07	07	32		02
23.	Haryana	33	17	75	58	03
24.	Punjab	20	15	154	84	01
25.	Himachal Pradesh	120	18	175	339	01
26.	J & K					
	Total	**2732**	**390**	**7312**	**15036**	**77**

अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन – 20–21 सितंबर, 2008, पटना

सोची समझी रणनीति के तहत देश में घुसपैठ

– सुब्रमण्यम स्वामी

बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण देश में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह देश की जनसंख्या को बदलने की साजिश है। अगर इसी प्रकार घुसपैठ जारी रही तो देश में हिन्दू बहुमत में नहीं रहेगा। घुसपैठ हमारे देश के लिये एक सोची समझी रणनीति है लेकिन इन रणनीति बनाने वाले लोगों को अपनी मंशा में सफल नहीं होने देंगे। ये बातें पूर्व केन्द्रीय कानून मंत्री डॉ0 सुब्रमण्यम स्वामी ने पटना में आयोजित अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन के उदघाटन समारोह में कही। श्री स्वामी ने कहा कि बांग्लादेशी यहां तभी रहेंगे जब बांग्लादेश पुरी तरह हिन्दुस्तान में होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 3 करोड़ घुसपैठिये के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराने की मांग बांग्लादेश से होनी चाहिए। अगर जमीन मुहैया नहीं कराई जाती है तो भारत सरकार अपनी सैन्य शक्ति के आधार खुलना से सिलेट तक की जमीन कब्जा ले इससे घुसपैठ पर रोक लगेगी। श्री स्वामी ने कहा कि हिन्दुस्तानी के पास शक्ति है परन्तु ये चेतना के अभाव में सर्कस के सिंह के तरह कुछ कर नहीं पाते। हम चाहकर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पाते।

उन्होंने कहा कि देश में आंतकवाद, पशु तस्करी, जाली नोटो का धंधा, मानव व्यापार इन्हीं घुसपैठियों की देन है। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आकर खड़ी हो गई है। बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णियां सहित आसाम, प. बंगाल एवं त्रिपुरा जैसे राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण भयानक संकट उत्पन्न हो चुकी है। उन्होंने कहाकि आने वाले समय में यदि इन पर रोक नहीं लगायी गई तो देश एक और टुकड़ों में बंट जाएगा। आज देश के छात्रों को आगे आकर लड़ना होगा तभी हमारा देश टुटने से बच सकता है। उदघाटन समारोह को राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 रामनरेश सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट, आंदोलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्री. सुनील बंसल, स्वागताध्यक्ष डॉ0 रणवीर नंदन, प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 विनोद राय ने भी संबोधित किया। समारोह का मंच संचालन बिहार के प्रदेश मंत्री राजेश सिन्हा ने किया।

अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन में पारित प्रस्ताव

भारत में अवैध रूप से लगातार बढ़ती जा रही बांग्लादेशी घुसपैठ देश में आंतरिक अस्थिरता उत्पन्न करने वाला बाह्य आक्रमण है। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी हो या दिल्ली न्यायालय ने प्रतिदिन 100 घुसपैठिये को देश से बाहर निकालने का कड़ा निर्देश हो, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायधीश द्वारा राज्य सरकार की घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली प्रोत्साहन नीति की कड़ी आलोचना करते हु यहां तक कहना कि बांग्लादेशी आज असम में किंग मेकर की भूमिका में आ गये हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक श्री प्रकाश सिंह द्वारा भारत के गृहमंत्री को चेताते हुए यह कहना कि घुसपैठ व आंतकवादी गतिविधियों के कारण उत्तर–पूर्वी भारत में भी जम्मू–कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। तो वहीं पूर्व थल सेनाध्यक्ष श्री शंकर राय चौधरी द्वारा राज्यसभा में गैरकानूनी घुसपैठ के बारे में कहना कि बांग्लादेश की राजनीतिक सीमायें भारत की सीमाओं में 10–20 कि.मी. अंदर तक घुस आयी है तथा बांग्लादेश आई.एस.आई. की गतिविधियों के लिए आधारभूत स्थान है।

अभाविप का यह छात्र नेता सम्मेलन देश के प्रमुख न्यायलयों एवं व्यक्तियों द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ पर की गई टिप्पणियों को गंभीरता से स्वीकार करता है साथ ही इस सम्मेलन का सुविचारित मत है कि देश में मौजूद करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जनसंख्या असंतुलन, जमीनों पर अवैध कब्जे, मादक द्रव्य, पशुधन, हथियार, महिला तथा

जाली नोटों की तस्करी जैस जघन्य अपराधों के साथ ही अंतराष्ट्रीय इस्लामिक आंतकवाद अलकायदा, आई.एस.आई. और बांग्लादेशी गुप्तचर संस्था जी.डी.एफ.आई. द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षित और पोषित हुजी व सीमी जैसे आंतकवादी संगठन मानवता विरोधी पैशाचिक कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। जयपुर, अहमदाबाद, बंगलूर और दिल्ली में पूरे देश ने इनके कृत्यों को देखा है।

यह छात्र नेता सम्मेलन घुसपैठ से उत्पन्न खतरों को गंभीरता से लेते हुए इसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिएए चुनौती मानता है। घुसपैठ एवं आंतकवाद द्वारा देश के सार्वजनिक स्थान, प्रतिष्ठानों और प्राण रक्षा केन्द्र अस्पतालों तक को निशाना बनाकर देश में अस्थिरता एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं। एक ओर देश आतंक एवं घुसपैठ से ग्रस्ति है वहीं ऐसे संकट की घड़ी में सत्ता लोलुप राजनीतिक नेता व केन्द्र सरकार अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने में लिप्त है। देश के इन राज नेताओं में तुष्टिकरण की होड़ मची है। सरकार द्वारा सीमी के खिलाफ सबूत पेश नहीं करना, लालू प्रसाद एवं मुलायम सिंह यादव द्वारा सीमी की वकालत करना, दिल्ली एवं असम राज्य के मुख्यमंत्री तरूण गोगई द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ को सिरे से खारिज करना तथा वोट बैंक के मसीहा बनने के लिए रामविलास पासवान द्वारा घुसपैठियों को नागरिकता देने की खुले आम राष्ट्रद्रोही मांग करना। यह दर्शाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारतीय नागरिक होने के प्रमाण भी इन्हीं राजनीतिक नेताओं के संरक्षण के चलते हथियाये हैं।

बांग्लादेशी घुसपैठ समस्या किसी एक प्रान्त तक सीमित न होकर राष्ट्रीय समस्या है। भारत में अवैध घुसपैठ के जरिये जनसंख्या संतुलन बिगाड़ कर आसाम सहित समूचे पूर्वांचल, बंगला, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड के जिलों को जोड़ कर मुस्लिम देश बनाने का षडयंत्रकारी सपना है, जो कि भारत की अखंडता एवंसंप्रभुता पर हमला है। भारत को समग्र उत्तर–पूर्वांचल से जोड़ने वाला गलियारा **चिकन नेक** पर मुस्लिम घुसपैठियों की आबादी घनीभूत (9.1) कर ने केवल जनसांख्यिक संतुलन को बिगाडा है अपितु देश की सुरक्षा को ही नाजूक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह सम्मेलन सरकार से मांग करता है कि देश की सुरक्षा के लिए चिकन नेक गलियारे को तत्काल प्रभाव से घुसपैठियों से खाली करवाए।

अ.भा.वि.प. का यह छात्र नेता सम्मलेन सरकार एवं राजनीतिक दलों को आगाह करना चाहता है कि वे तुष्टिकरण की नीति छोड़ कर बांग्लादेशी घुसपैठ के पीछे के विस्तारवादी इतिहासिक षडयंत्र को समझें। साथ ही केन्द्र सरकार घुसपैठियों से निपटने के लिए कठोर कानून बनायें व उन्हें तुरंत मतदाता सूची से हटा कर देश बाहर करने की कार्यवाही करो।

यह छात्र नेता सम्मेलन देश के आम जनता व विशेषकर युवा शक्ति से आह्वान करता है कि घुसपैठ की इस गंभीर चुनौती को स्वीकार करें तथा घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले तथाकथित सकूलरवादी दलों एवं नेताओं की नीतियों का पर्दाफाश करें तथा एकजूट होकर घुसपैठियों का आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार करें व राजनैतिक दलों व सरकारों पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्यवाही करने का दबाव निर्माण करें।

यह सम्मेलन केन्द्र सरकार से घुसपैठ की इस समस्या के समाधान के लिए निम्न मांगें करता है:–

1. समूचे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में से हटाने और उन्हें देश के बाहर भेजने की समयबद्ध कार्यवाही की व्यवस्था की जाये। (Detect-Delete-Deport)
2. बांग्लादेश से लगी भारतीय सीमा में तारबंदी अतिशीघ्र पूरी कर सुरक्षा के उचित प्रबन्ध करें।
3. सीमा सुरक्षा बलों को घुसपैठियों को रोकने के लिए व्यापक अधिकार दिये जाये व सीमा पर के जवानों एवं चौकियों की संख्या बढ़ायी जाये।
4. पूर्वात्तर भारत को जोड़ने वाला सुरक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील गलियारा **'चिकन नेक'** को घुसपैठियों से तुरन्त खाली कराया जाये एवं विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाकर उसे नियंत्रित किया जाये।
5. देश में बढ़ रही आंतकवादी घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कानून बनाने एवं घटनाओं की पुनरावृति को रोकने हेतु उपाय किये जायें।
6. सीमा क्षेत्र में बढ़ रही अपराधियों को रोकने हेतु कठोर कार्यवाही की जाये। विशेष रूप से गाय, हथियार एवं मादक पदार्थ की तस्करी को तुरंत प्रभाव से रोका जाये।
7. बांग्लादेश सरकार पर इन घुसपैठियों को वापस लेने हेतु भारत सरकार द्वारा राजनैतिक दबाव बनाया जाये।

अखिल भारतीय छात्र नेता सम्मेलन के मध्यम से देश की छात्र शक्ति पुनः यह संकल्प करती है कि :–

- घुसपैठियों से मातृभूमि को मुक्त करने तक यह आन्दोलन जारी रहेगा।
- इसके लिए देशव्यापी जनआन्दोलन खड़ा करेंगे।
- आज की पीढ़ी इस निर्णयक संघर्ष में अपनी सक्रिय भूमिका निभायेगी। ■

जामिया एनकाउंटर और मुस्लिम पहचान

– आशुतोष –

मैंने अनवर से पूछा – तुम क्या कर रहे हो?

उसने पलटकर पूछा – इसका क्या मतलब ?

मैंने कहा – अबे जामिया में ये ी करने की क्या जरूरत है? तुम क्यों नहीं समझते? इससे गलत संदेश जाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो।

ये सुनते ही अनवर आपा खो बैठा और बोला- तुम्हारा क्या मतलब है? कानूनी सहायता देना मूलभूत अधिकार है। मैं उस पर भला कैसे आपत्ति कर सकता हूं। मैंने कहा-देखो ए कोई भी भला आदमी इस बात पर उंगली नहीं उठाएगा पर यह वह समय नहीं है। ऐसे में जब कोई ये नहीं ता कि कहां बम फटेगा और हम घर लौटेंगे भी या नहीं तब आप कैसे किसी से समझदारी की उम्मीद कर सकते हैं।

आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों 20वीं सदी के बेहरतीन दिमागों में से एक सलमान रुश्दी खुली हवा में सांस नहीं ले सकते और क्यों तसलीमा नसरीन देश की सबसे धर्मनिरपेक्ष मानी जाने वाली लेफ्ट सरकार के साए में शांति से नहीं रह सकतीं? आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह सिमी पर से बैन हटाने को सही ठहराने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि देवबंद के मौलाना मदनी रामलीला मैदान में आतंकवादी विरोधी रैली का आयोजन करते हैं और आतंकवाद का विरोध करते हैं तो उर्दू प्रेस उनकी आलोचना पर उतर आती है ?

काफी देर गर्मागर्मी होती रही। एक बार तो ऐसा लगा कि दोस्ती खतरे में है। अनवर और मैं 1988-90 में जेएनयू में साथ-साथ थे। तब से हम परिवार की तरह हैं। हमारे बीच कई बार काफी नोंकझोंक होती रही और ढेरों मुद्दों पर हमारे विचार काफी अलग-अलग ही रहे लेकिन कभी भी हमारी दोस्ती पर आंच नहीं आयी।

बहसाबहसी में मैंने महसूस किया कि हमारे गुस्से के कारण कुछ और है शायद हम एक दूसरे से जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। मैं शायद ये कहना चाहता था कि मुसलमानों के साथ कुछ गड़बड़ है। तुम लोग हमेशा बम फोड़ते हो और वह शायद यह कहना चाहता था कि सरकारी अमले और मीडिया में हिंदुओं का बोलबाला है, जो हमेशा ये सोचते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए इसलिए निर्दोष मुस्लिम आतंकवाद के नाम पर निशाना बनते हैं।

यह वास्तव में अजीब था क्योंकि कट्टरवाद और फिरकापरस्ती से लड़ने का हम दोनों का लंबा इतिहास रहा है। हम दोनों ऐसी ताकतों के खिलाफ जोरदार ढंग से आवाज उठाते रहे हैं। तो फिर ये गरमागर्मी क्यों? मुझे अगली सुबह इस बात का जवाब मिल गया जब मैंने वरिष्ठ पत्रकार और लेजेंडरी संपादक एम जे अकबर का लेख पढ़ा। अकबर ने बड़े दबे छुपे शब्दों में उस बात को लिख मारा जो अनवर नहीं कह पाया। मैं ये साफ कर दूं कि एम जे के प्रति हमेशा से मेरे मन में सम्मान रहा है, जो आज भी है। वे आधुनिक और बेहतर समझ वाले चुनिंदा संपादकों में से एक हैं। लेकिन टाइम्स आफ इंडिया में रविवार को जो उन्होंने लिखा उसमें और शाह इमाम बुखारी के मुखर बयानों में काफी कुछ समानता मुझे दिखी।

मैं काफी निराश, उदास और परेशान था। मैं जवाब तलाश रहा था। क्या मेरी सोच में कहीं कुछ गड़बड़ है? क्या

मैं बदल गया हूं? क्या मैं वही आदमी हूं जो अबतक हिंदू सांप्रदायिकता और उसकी मुस्लिम विरोधी विचारधारा का विरोध करता आया है? आखिर, क्यों मैं अनवर और एम जे की विश्वसनीयता पर शक कर रहा हूं।

सोचते वक्त मुझे जाने-माने पटकथा लेखक जावेद अख्तर का खयाल आया, जिन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान मेरे एक मंझे हुए एंकर संदीप चौधरी को यह कहकर झिड़क दिया था कि उनका सवाल सांप्रदायिक है। मुझे ठीक से उनका वह सवाल याद नहीं लेकिन इतना याद है कि वह सवाल मुसलमानों और उनकी पहचान को लेकर था। तब मैंने गुस्से में एक हिंदी मैगजीन में एक तीखा लेख लिखा था और सवाल उठाया था कि क्यों आरिफ मोहम्मद खान को सैयद शहाबुद्दीन से 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में मात खानी पड़ी? आखिर क्यों ऐसा हुआ कि वी पी सिंह ने आरिफ मोहम्मद खान को इलाहाबाद जाने से रोक दिया जहां से वे 1988 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे लेकिन शहाबुद्दीन का स्वागत किया गया।

अचंभे की बात है कि मुझे इस मुद्दे पर जावेद अख्तर के कभी दोस्त रहे सलीम खान से जोरदार समर्थन मिला। उन्होंने दैनिक भास्कर में मेरे लिखे का हवाला देते हुए एक लेख लिखा था और मेरे कुछ तर्कों से सहमति जताई थी।

मुझे यहां ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले काफी समय से मेरे जेहन में ये सवाल रह रह कर गूंज रहा है कि अब मुस्लिम समुदाय के आत्ममंथन का वक्त आ गया है। समुदाय को खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या अंदर कहीं कुछ गलत हो रहा है?

आखिर क्यों नैरोबी से दार-ए-सलामए इंडोनेशिया से सूडान, मैड्रिड से मैनहटन, काबुल से कश्मीर, चेचेन्या से चीन तक उनकी पहचान एक ऐसे शख्स की बन रही है जो बम फोड़ता है, धमाका करता है?

मुझे मालूम है कि ऐसा कह कर मैं क्या जोखिम मोल ले रहा हूं। मुझे मालूम है कि कुछ लोग यकायक कह उठेंगे कि देखा आशुतोष का चेहरा बेनकाब हो गया, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में वो अबतक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा था। यही है उसका असली चेहरा। अब उसकी हकीकत सामने आई है। लेकिन मुझे आज इसकी परवाह नहीं।

आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों 20वीं सदी के बेहरतीन दिमागों में से एक सलमान रुश्दी खुली हवा में सांस नहीं ले सकते और क्यों तसलीमा नसरीन देश की सबसे धर्मनिरपेक्ष मानी जाने वाली लेफ्ट सरकार के साए में शांति से नहीं रह सकती? आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह सिमी पर से बैन हटाने को सही ठहराने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि देवबंद के मौलाना मदनी रामलीला मैदान में आतंकवादी विरोधी रैली का आयोजन करते हैं और आतंकवाद का विरोध करते हैं तो उर्दू प्रेस उनकी आलोचना पर उतर आती है?

कोई ये सवाल भी उठा सकता है कि कट्टरपंथ और फिरकापरस्ती तो हर धर्म में है तो ये हंगामा क्यों? मैं मानता हूं लेकिन थोड़ा फर्क है। हिंदू समाज में अगर भड़काने वाली कट्टरपंथी आवाज है तो वहीं इसके बराबर या कहें इससे भी अधिक मजूबत उदारपंथी आवाज भी है। ईसाईयत में ये जंग धार्मिक कट्टरपंथ काफी पहले हार चुका है। ईसाईयत में तय हो चुका है कि धर्म निजी आस्था का मामला है और राजनीति में मजहब के लिये कोई जगह नहीं है। हिंदुत्व और ईसाईयत में अबुल अल मौदूदी जैसे लोग नहीं दिखाई पड़ते जो धर्म और राजनीति का घालमेल करना चाहते हैं। मौदूदी दावा करते हैं कि इस्लाम एक क्रांतिकारी विचारधारा है और एक सिस्टम भी जो सरकारों को पलट देता है।

मेरी नजर में मुस्लिम समुदाय में रैडिकल इस्लाम या राजनीतिक इस्लाम है जो खुद अपने ही लोगों और दुनिया के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि इस तथाकथित रैडिकल इस्लाम के खिलाफ कोई पुरजोर आवाज बुलंद नहीं करता न ही भारत में और न ही दूसरी जगहों पर। उदारपंथियों का एक बड़ा तबका अक्सर चुप रहता है या फिर वह इसका इतनी ताकत से विरोध नहीं करता कि पूरा समुदाय इसको सुने।

फरीद जकरिया ने अपनी किताब 'पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड' में लिखा है कि मुस्लिम जगत भी बदल रहा है लेकिन बाकी की तुलना में काफी धीमे। इसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो इस बदलाव के विरोध में खडे हो खुद को इस तबके का नेता मानने का अहसास पाले बैठे हैं। दूसरी संस्कृतियों की तुलना में इस्लाम के अंदर प्रतिक्रियावादी ज्यादा कट्टर हैं- इनमें जड़ता व्याप्त है। हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। काफी अल्पसंख्या में हैं।

मैं मानता हूं कि मौदूदी जैसे लोग कम संख्या में हैं। नहीं तो अनवर, साजिद और आफीन जैसे मेरे दोस्त नहीं होते लेकिन बदकिस्मती से वे ऐसे कुछ लोगों को बाकी लोगों पर राज करने का मौका देते हैं। मुस्लिम समुदाय के बहुसंख्यक तबके की ये चुप्पी तकलीफदेह है और अब यह चुप्पी काफी जटिल रूप अख्तियार करती जा रही है। यह इसी 'कांप्लेक्स'

का नतीजा है कि जामिया नगर का 'पुलिस एनकाउंटर' मुस्लिम बौद्धिक वर्ग के लिये अपनी मुस्लिम पहचान बनाने का जरिया बन जाती है।

मेरा सवाल यह है कि आखिर क्यों एक एनकाउंटर को मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमला माना जा रहा है? पुलिस एनकाउंटर कोई नया नहीं है। ये असली या फर्जी दोनों ही होते है। यह हर रोज होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब कोई आतिफ अमीन मारा जाता है तो हंगामा हो जाता है, प्रदर्शन होते हैं। यहां कोई नंदू मारा जाता है तब जंतर-मंतर और जामिया पर रैली क्यों नहीं होती?

मुझे एम जे अकबर को ये बताने की जरूरत नहीं कि एक नकली एनकाउंटर को असली बनाने के लिए पुलिसवाले अकसर खुद को गोली मारते हैं? राजबीर, दया नायक और प्रदीप शर्मा असली गोली चला कर हीरो नहीं बने बल्कि ये अकसर उन लोगों को मारकर हीरो बने है जिनको इन्होंने पकड़ कर रखा था। मोहनचंद शर्मा भी कोई साधू नहीं था लेकिन एमजे को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि जामिया नगर एनकाउंटर में एम सी शर्मा पुलिस की गोलियों का भी शिकार हो सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या वो एक आम मुसलमान की तरह 'रिऐक्ट' कर रहे हैं या फिर देश के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। यही सवाल मेरा अपने प्रिय मित्र अनवर से भी है।

मेरा सवाल यह है कि आखिर क्यों एक एनकाउंटर को मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमला माना जा रहा है? पुलिस एनकाउंटर कोई नया नहीं है। ये असली या फर्जी दोनों ही होते हैं। यह हर रोज होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब कोई आतिफ अमीन मारा जाता है तो हंगामा हो जाता हैए प्रदर्शन होते हैं। यहां कोई नंदू मारा जाता है तब जंतर–मंतर और जामिया पर रैली क्यों नहीं होती?

ये मेरा अनुमान नहीं बल्कि यकीन है कि दोनों महानुभाव एक नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उनके शब्दों में वही कुछ झलक रहा है जो कि जमिया नगर, सराय मीर और आजमगढ़ की सड़कों पर आम मुसलमान की बातों में झलक रहा है। यहां खुले रूप से कहा जा रहा है कि 'काउंटर टेररिज्म' के नाम पर मासूम मुस्लिमों को शिकार बनाया जा रहा है। पहले आम मुसलमान और पढ़े-लिखे मुसलमान में फर्क था। लेकिन अब ये तस्वीर कुछ-कुछ धुंधली होती दिख रही है और ये बात परेशान करने वाली है।

भारतीय संदर्भ में क्या इसका ये मतलब है कि मुस्लिम समुदाय में उदारता कम होती जा रही है? मेरा जवाब है - बिग नो । फिर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों? मैं इसे 'लिटिल ब्वाय सिंड्रोम' कहता हूं। एक ऐसा बच्चा जिसे बार-बार उस शैतानी के लिए दोषी ठहराया जाता है जो उसने की ही नहीं। अवसाद के चलते वह जिद्दी और हठी हो जाता है - स्वीकारतावादी। और वो चिढ़ कर या तंग आकर, परेशान होकर कह उठता है-'हां मैंने ही किया है। आप क्या कर लोगे?'

तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने और अल कायदा और ओसामा बिन लादेन के उभरने के बाद से उदारपंथी मुसलमानों के दिक्कतें शुरू हो गयीं, उनकी पहचान को खतरा पैदा हो गया है। दुनिया के हर कोने में उन पर लगातार नजर रखी जा रही हैं। उनका नाम आते ही उन्हे 'अजीब सी नजरों' से देखा जाता है मानो वो आम इंसान न होकर आतंकवादी हों। न्यूयॉर्क हो या नई दिल्ली सब जगह यही हाल है। एक उदारपंथी मुसलमान जानता है कि उसका कट्टरपंथियों की सोच से कोई लेना देना नहीं है। उसका बम फोड़ों आंतकवादी सोच से दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। न ही वो ये मानता है कि हिंदू- यहूदी-ईसाई या भारत-इस्राइल-अमेरिका इस्लाम को नेस्तनाबूद करने के लिये साजिश रच रहे हैं। लेकिन वो कर क्या सकता है। वो असहाय है। उसे मालूम है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं। वो अंदर भी टूट रहा है और बाहर भी उनपर कोई यकीन नहीं कर रहा है कि ये खतरनाक सोच उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और यही असहायता उसके अंदर एक ऐसे कांप्लेक्स को जन्म देती है जिसे हम लिटिल ब्वाय सिंड्रोम कहते है।

अनवर मेरे दोस्त, तुम्हें इस सिंड्रोम से बाहर आना होगा क्योंकि अगर तुम मौदूदी और सैयद कुतुब और ओसामा और जवाहिरी जैसी सोच का शिकार हो गए तो इस धर्म का कोई भविष्य नहीं बचेगा जो शांति और क्षमा का पाठ पढ़ाता है। इस आततायी मानसिकता का जोरदार विरोध करने का वक्त आ गया है। अगर अब ऐसा नहीं होगा तो मैं, तुम और एम जे जैसे लोग इतिहास में विलेन के रूप में देखे जाएंगे और हिंदू कट्टरपंथी जैसी ताकतें इस देश पर राज करेंगी। ■

Professional Education Under Political Pressures

– J.S. Rajput –

Brilliant contributions of young Indians in different areas of new knowledge have given India a new global image. The entire world realizes that India is capable of exporting 'knowledge' at its highest level. Practically every significant multinational greatly values the services of is young Indians. Credit must accrue to Indian institutions of professional and higher education, though Indian institutions rarely figure in the lists of best institutions of the world. Indian achievements defy several weak points of the education system. India is far behind in becoming an international education hub. While around 80,000 students go abroad for higher education every year, only around 8000 come to India, the major chunk being that of the students of Indian origin. Only around 10% of the young persons in the age group 18-23 are in the fold of higher education. China stands at 20% participation. The global average is around 20-22 per cent and the participation rates are far higher in the developed countries. None can however, deny the fact that IIMs and IITs are brand names known throughout the globe.

The first phase of institution building, initiated by Jawaharlal Nehru and the scientists who enjoyed his full confidence has delivered the results. India has conducted researches and initiated technological breakthroughs with total dedication to 'humane considerations.' This country has always valued knowledge and the knowledgeable. Knowledge is the key to prosperity ahead. India now needs to embark upon the second phase of institution building. The MHRD has made encouraging announcements during the last couple of years. Almost doubling the numbers of IIT's and IIM's coupled with the opening of 30 new central universities, more colleges and more schools could gladden the hearts of everyone who believes in the criticality of good quality education for the larger number of young persons for sustainable growth and development. Somehow, the manner of implementation, the way it is emerging in public domain, creates serious doubts on how quality levels on par with the existing counterparts could be achieved?

The total collapse of regulatory mechanisms, set up to maintain quality in higher education, is no secret. Even the MHRD went to the extent of proposing the annulment of the National Council for Teacher Education (NCTE) Act. MHRD has instructed its premier regulatory bodies in higher education to be tough with the universities and the colleges making false claims. In fact the functioning of most of the colleges and universities, particularly the deemed and private universities has been a cause of serious concern amongst academicians and teachers who are still not mesmerized by the glamour of the globalized education network. This is the fast decreasing category of those who still despise coaching but are ever ready to assist their students in the traditional Indian relationship between the teachers and taught. These academics have seen the fast-paced decline of the regulatory functioning of several national level bodies. They lamented approvals granted to 'colleges and universities', which did not present even a semblance of readiness to perform the .....

(Continues at Page No. 24)

मुलाकात

श्री. श्रीनिवास
(राष्ट्रीय सचिव, अभाविप)

प्रखर वक्ता एवं युवाओं के उर्जास्रोत श्री.श्रीनिवास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय सचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हाल ही में ताजा घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए 'उमाशंकर मिश्र' उनसे विस्तृत चर्चा की। प्रस्तुत हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश.

हाल ही में दिल्ली में एसएआर गिलानी पर अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करते हुए मुंह पर थूक दिया गया। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद् के पास तर्क चुक गए हैं?

सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना विद्यार्थी परिषद् की नीति नहीं है। तर्क खत्म नहीं हुए हैं। यह नहीं भूलना चाहिए जिस गिलानी का विरोध करने के लिए विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता गए थे, उसने आज तक संसद पर हुए हमले को लेकर विरोध व्यक्त नहीं किया है। यह बात अलग है कि सबूतों एवं गवाहों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। वही गिलानी गत दिसंबर में एक ऐसे मामले की परिचर्चा में बोलने कुरूक्षेत्र गए थे। चर्चा का विषय था 'अफजल को फांसी उचित या अनुचित'। क्या यह कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या इस तरह के तथ्य गिलानी को कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं? विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने कुरूक्षेत्र में भी गिलानी का विरोध किया था और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। परिषद् कार्यकर्ताओं एवं समस्त राष्ट्र के लिए यह एक भावनात्मक मुद्दा है। राष्ट्रद्रोह की सारी सीमाएं लांघने वाले व्यक्ति को सरेआम घूमने देने के लिए एवं उसका विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज करने के लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूं। यह दोहरा मापदंड विद्यार्थी परिषद् के साथ अपनाया जा रहा है। इस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए।

रामसेतु को 14 सितंबर तक न ढहाए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी। वर्तमान परिस्थिति क्या है और उस पर परिषद् की क्या प्रतिक्रिया है?

रामसेतु को बचाने के लिए चलाए गए अभियान के चरण में आरंभ से लेकर अब तक कई मोड़ आए हैं। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने देश के समूचे जनमानस को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है क्योंकि भारतीय हिन्दू जनमानस की आस्था के प्रतीक श्रीराम के अस्तित्व पर ही तथाकथित सेकुलरवादियों ने सवाल खड़ा कर दिया था। जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने विरोध का मन बना लिया। इस अभियान के बाद केन्द्र सरकार ने कदम पीछे हटाना ही ठीक समझा। टीआर बालू का तो व्यापारिक हित भी इस मामले से जुड़ा हुआ है। इस कड़ी में टर्निंग प्वाइंट तब आया, जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया। इससे सेकुलरवादियों की निचली जमात के लोगों का मन भी आहत हो गया। यही कारण था कि 12 सितंबर को देश भर में रामसेतु को बचाने के लिए किए गए देशव्यापी आंदोलन में स्थानीय स्तर पर इन धर्मनिरपेक्ष दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में शामिल होकर सहयोग किया। यहां हर निर्णय वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया जाता है, यही कारण है कि सरकार पीछे हट गई।

ऐसा ही दूसरा उदाहरण अमरनाथ का है, अलगाववाद के नाम पर सरकार पिछले 60 सालों से झुकती आ रही है। अमरनाथ श्राईन बोर्ड को जमीन दिए जाने के मसले पर एक बार फिर सरकार ने अलगाववादियों के समक्ष घुटने टेक दिए। वास्तव में यह मुद्दा केवल जमीन का नहीं था बल्कि इसके पीछे एक सोच है। कश्मीर पर कब्जा करना और उसे पाकिस्तान में मिलाना उसी सोच का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ समय से हिन्दु यात्रियों की संख्या में वृद्धि

हो रही थी, जिससे आईएसआई एवं अलगाववादी सकते में आ गए। भूलना नहीं चाहिए कि 1990–91 में लाखों कश्मीरी हिन्दुओं को घाटी से निकाल दिया गया और भीषण रक्तपात हुआ था। यह कश्मीर को भारत से काटने के लिए ही किया गया था। लेकिन इस बार अमरनाथ संघर्ष समिति ने इसके विरोध ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ा और हिन्दू जनमानस में आई जागरुकता से धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मुंह की खानी पड़ गई।

'हिन्दू आतंकवाद' नामक शब्द हाल ही में चर्चा में आया है। क्या कहेंगे आप इस पर?

आतंकवाद की बात दुनिया के किसी हिस्से में होती है तो इस्लाम का चेहरा पहले सामने आता है। यही कारण है कि हिन्दुओं को आतंकवादियों की श्रेणी में खड़ा करने का षडयंत्र रचा जा रहा है। जिससे यह कहा जा सके कि इस्लाम ही नहीं हिन्दु भी आतंकवादी हैं। राजनीति हमारे यहां इस कद्र पतित है कि यह कहने में किसी को गुरेज नहीं होता कि 'इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है।' बिहार में तो हर थाने में एक मुस्लिम दरोगा रखे जाने की बात कही जा रही थी। क्या यह सब कवायदें देश को जातीय आधार पर बांटने की साजिश नहीं है? जहां तक हिन्दू आतंकवाद की बात है तो यह एक मिथ है, गढ़ा गया है। निर्दोष लोगों की हत्या हिन्दू मानसिकता का हिस्सा नहीं हो सकता।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभाविप की याचिका पर संज्ञान लेते हुए एससी, एसटी छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर 12 राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है? छात्रावासों के हालात कैसे हैं?

समाज कल्याण विभाग के एससी, एसटी छात्रावासों का अभाविप ने सर्वेक्षण किया और पाया कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी छात्रों को तरसना पड़ता है। छात्राओं के लिए नहाने का स्थान तक नहीं है और शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। राशन की व्यवस्था दुरूस्त नहीं है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट छात्रावासों के नाम के साथ प्रकाशित किया गया। अधिकारियों ने भी इन छात्रावासों का दौरा किया। आंध्रा में एससी/एसटी स्कोलरशिप के लिए प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद् कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन इसका दबाव इतना पड़ा कि सरकार को झुकना पडा

अभाविप ने 12 नवंबर को देशव्यापी कॉलेज बंद का आह्वान कर रही है, इससे विद्यार्थी परिषद् क्या संदेश देना चाहती है?

बांग्लादेशी घुसपैठ देश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते इस पर राजनीतिक पार्टियां कदम उठाने से पीछे हट रही हैं। जिसका खामियाजा सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हजारों भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों के संसाधनों पर बांग्लादेशियों ने कब्जा जमा लिया है। अभाविप ने इस मामले को लगातार उठाया है और आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक ले जाने के लिए इस तरह का विशाल आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया है। इसकी परिणति से सरकार भयभीत है क्योंकि निचले स्तर तक आंदोलन प्रभावी होगा। विभिन्न स्थानों पर हमें छात्रों का समर्थन इस मुद्दे पर मिल रहा है। यह आंदोलन विद्यार्थी परिषद् के स्वरूप एवं उसकी ताकत को भी बताएगा। अगले चरण में 17 दिसंबर को 50 हजार छात्र देश भर से बिहार के चिकननेक नामक स्थान पर एकत्रित होंगे जहां 90 प्रतिशत बांग्लादेशी घुसपैठिये रह रहे हैं और भारतीयों की संख्या महज 10 प्रतिशत है। यदि वह भारतीय वहां नहीं रहे तो पूर्वोत्तर से भारत का संपर्क कट जाएगा। सरकार का ध्यान इस ओर जाए और वह इस गंभीर समस्या पर कठोर से कठोर कार्यवाही करे यही हमारा मकसद है, जिससे देश की अखंडता तार तार होने से बची रहे।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एवं रोजगार संबंधी चुनौतियों पर आपका क्या दृष्टिकोण है?

शिक्षा व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन की जरूरत है। पूरी दुनिया के देशों से पाठ्यक्रमों की खिचड़ी बनाकर भारतीय छात्रों को परोसी जा रही है। जिसमें सूचना मात्र है, ज्ञान नहीं है। किसी भी देश में मानव संसाधन वहां की अनमोल पूंजी होता है। उसके विकास के लिए आज भारत में एक अनुकूल ढांचा बनाए जाने की जरूरत है। इस बात को हमने बहुत पहले 2002 में एक विशाल रैली कर बताया था। रोजगारपरक शिक्षा समय की मांग है। केन्द्र सरकार सेवा क्षेत्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था रूपी ताश के पत्तों का जो महल खडा करने की कोशिश की थी वह आर्थिक मंदी के कारण धम्म से नीचे आ गिरी है। सेवा क्षेत्र में रोजगार तलाशने की बजाय उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन आज इस देश की आवश्यकता है। आतंकवाद की एक कड़ी के रूप में आर्थिक आतंकवाद को भी देखा जा सकता है। आज हर तीसरा व्यक्ति इस बात को लेकर भयभीत है कि कब उसे नियोक्ता की ओर से नौकरी छोड़ने का हुक्म मिल जाए। एससी गुप्ता कमेटी ने कुछ समय पूर्व जो सिफारिशें की थी, आज उन्हें लागू करने की जरूरत है। उद्योग एवं शिक्षा के अंर्तसंबंधों को विकसित करना होगा जिससे युवाओं को बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार के उपयुक्त अवसर भी प्राप्त हो सकें। ■

कंधमाल प्रकरण और मीडिया का द्वंद

– आशुतोष भटनागर –

हत्यारों की रायफलें आग उगलती हैं और 84 वर्ष के एक वयोवृद्ध सन्यासी की जान ले लेती हैं। वनवासी समाज में प्रतिक्रिया होती है और राज्य व केन्द्र की सरकारें उसे कुचल डालने का इरादा जताती हैं। चर्च समर्थक प्रतिनिधिमंडल मृत सन्यासी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करता है, उसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक भी करता है। पुलिस घटना के मिनटों बाद ही बिना जांच के हत्याकांड में माओवादियों का हाथ होने की सूचना प्रसारित कर जांच को टकाने की कोशिश करती है। वेटिकन से पोप धमकाते हैं तो इटली की सरकार भारतीय राजदूत को फटकारती है। ब्रिटेन और अमेरिका की संसद में ईसाइयों के साथ हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त करती है, यूरोपियन यूनियन की बैठक में भारत में हो रहे ईसाइयों के सामूहिक नरसंहार पर प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को आड़े हाथों लिया जाता है। क्षुब्ध लोगों की प्रतिक्रिया को देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शर्म बताता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोहराता भी है। राजनेताओं के बीच चर्च के समर्थन में खड़े होने की होड़ मच जाती है। मानवाधिकार कार्यकर्ता, विदेशी पैसे पर पलने वाले गैर सरकारी संगठन चीखने–चिल्लाने लगते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ लेती है! डेढ़ माह बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिलता है।

स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या के बाद पूरे देश में समाचार जगत में जो प्रतिक्रिया दिखायी दी उसने कथित राष्ट्रीय मीडिया और भारतीय भाषाओं की मीडिया के चरित्र के अंतर को एक बार फिर स्पष्ट किया । स्थानीय समाचार पत्रों तथा ओड़िया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा दी गयी खबरों में जहां वस्तुनिष्ठता नजर आती है वहीं उनके संपादकीय में भी घटनाकम का तथ्यपरक विश्लेषण दिखाई देता है। कारण है कि उन्हें घटना का इतिहास भी मालूम है और जमीनी हकीकत भी। इसलिये तथ्यों को उनके वास्तविक संदर्भ में समझने के कारण स्थानीय मीडिया टकता नहीं है वहीं कथित राष्ट्रीय मीडिया अपने पूर्वाग्रहों के कारण समस्या की जड़ तक पहुंचने में सदैव असफल रहता है। ऐसा लगता है कि पत्रकारिता की दृष्टि को लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया के बीच एक द्वंद है जो उनकी प्राथमिकताओं और चरित्र को उजागर करता है।

स्थानीय समाचार पत्रों तथा ओड़िया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा दी गयी खबरों में जहां वस्तुनिष्ठता नजर आती है वहीं उनके संपादकीय में भी घटनाकम का तथ्यपरक विश्लेषण दिखाई देता है। कारण है कि उन्हें घटना का इतिहास भी मालूम है और जमीनी हकीकत भी। इसलिये तथ्यों को उनके वास्तविक संदर्भ में समझने के कारण स्थानीय मीडिया टकता नहीं है वहीं कथित राष्ट्रीय मीडिया अपने पूर्वाग्रहों के कारण समस्या की जड़ तक पहुंचने में सदैव असफल रहता है। ऐसा लगता है कि पत्रकारिता की दृष्टि को लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया के बीच एक द्वंद है जो उनकी प्राथमिकताओं और चरित्र को उजागर करता है।

एक अन्य पहलू है जवाबदेही का। ओड़िया मीडिया की जवाबदेही ओड़िया भाशी पाठकों और दर्शकों के प्रति है और वह पाठक स्थानीय होने के कारण कमो–बेश स्वयं भी तथ्यों से परिचित

है अतः उसे गलत तथ्य देकर अथवा आयातित विचार उस पर थोप कर उसे रमाया नही जा सकता। इसके विपरीत राजधानियों में बैठा मीडिया महारथियों का समूह, जो स्वयं को राष्ट्रीय मीडिया कहता है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान कमाने के लोभ में स्वयं को अनेक बार राष्ट्रीय सरोकारों से भी काट लेता है। स्वामी जी की हत्या के बाद ओडिया भाषा के समाचार पत्र तथा राज्य से प्रकाशित हो रहे अंग्रेजी अखबारों ने भी स्वामी जी द्वारा वनवासी इलाकों में गत चार दशकों से अधिक समय से चलाये जा रहे सेवा–साधना के कार्य को प्रकाशित किया ।

इन अखबारों ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को लेकर काफी खबरें प्रकाशित की। इसके अलावा इन अखबारों ने ईसाई समुदाय द्वारा पूर्व में स्वामी जी पर हुए हमलों का ब्योरा, स्वामीजी को दी जा रही सुरक्षा में कमी, मतातंरण की समस्या, गो हत्या प्रकरण पर समाचार प्रकाशित किये। मतांतरण और गो हत्या को बंद कराने के लिए स्वामी जी के प्रयासों की भी खबरें खूब छपी। मतांतरण के कारण जनसांख्यिकी में हो रहे परिवर्तन के बारे में भी खबरें स्थानीय मीडिया ने छापी। इसके अलावा आम लोगों पर पुलिस के अत्याचार की घटनाएं भी प्रकाशित हुई। इस हत्या के पीछे के लोगों के बारे में स्थानीय अखबारों ने खूब छापा। स्वामी जी की वर्वर हत्या पर संपादकीय लिखे गये तथा संपादकीय पृष्ठ पर अनेक लेख प्रकाशित किये गये।

वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय मीडिया ने विशेश कर समाचार चैनलों ने तथाकथित धर्मनिरपेक्षों व ईसाई दवाब समूहों के प्रभाव में अधिकतर एकतरफा चित्र ही प्रस्तुत किया। इन समाचार माध्यमों ने स्वामी जी की वर्वर हत्या के बाद प्रतिकिया स्वरुप हुई कुछ छुटपुट घटनाओं को अतिरंजित कर प्रस्तुत करना प्रारभं किया । स्वामी जी की हत्या के बारे में न तो कोई खास समाचार प्रस्तुत किया गया और न ही उनके विशाल व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताया गया। इन समाचार माध्यमों को बिलखती वनवासी बालिकाओं का रुदन सुनाई नहीं दिया। स्वामी जी की हत्या के पीछे के षडयंत्र के बारे में राष्ट्रीय मीडिया ने एक शब्द भी नहीं छापा।

ओडिसा के क्योंझर जिले में 1999 में विदेशी पादरी ग्राहम स्टेंस की हत्या की घटना पर आसमान सर पर उठा लेने वाले तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया के समाचार पत्रों तथा चैनलों ने स्वामी जी की बर्बर हत्या पर विशेष जानकारी देना तो दूर उनके व्यक्तित्व व कार्य के बारे में सही जानकारी भी देना उचित नहीं समझा। इन समाचार माध्यमों में कहीं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को एक कट्टरपंथी नेता बताया गया तो ज्यादातर ने उन्हें विहिप का नेता बताया। उनके विशाल व्यक्तित्व को छुपाने का प्रयास किया गया । लेकिन ओडिशा के प्रतिष्ठित उड़िया समाचार पत्रों ने स्वामी जी के कार्यों तथा उनकी हत्या के पीछे के चेहरों की ओर स्पष्ट संकेत किया तथा इसके पीछे छुपे गहरे षडयंत्र के बारे में सचेत किया।

ओडिसा के क्योंझर जिले में 1999 में विदेशी पादरी ग्राहम स्टेंस की हत्या की घटना पर आसमान सर पर उठा लेने वाले तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया के समाचार पत्रों तथा चैनलों ने स्वामी जी की बर्बर हत्या पर विशेष जानकारी देना तो दूर उनके व्यक्तित्व व कार्य के बारे में सही जानकारी भी देना उचित नहीं समझा। इन समाचार माध्यमों में कहीं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को एक कट्टरपंथी नेता बताया गया तो ज्यादातर ने उन्हें विहिप का नेता बताया। उनके विशाल व्यक्तित्व को छुपाने का प्रयास किया गया । लेकिन ओडिशा के प्रतिष्ठित उड़िया समाचार पत्रों ने स्वामी जी के कार्यों तथा उनकी हत्या के पीछे के चेहरों की ओर स्पष्ट संकेत किया तथा इसके पीछे छुपे गहरे षडयंत्र के बारे में सचेत किया।

राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित समाचार पत्र समाज ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि स्वामी जी की हत्या से निरंकश मतांतरण का रास्ता साफ हो गया है। निरंकुश मतांतरण के लिए रास्ता साफ शीर्षक वाले अपने विश्लेषण में अखबार ने लिखा– जनजाति समाज अभाव से ग्रस्त है, शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाएं पर्याप्त रुप से उन्हें प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा जनजाति समाज में कुछ कुसंस्कार तथा कुछ अंधविश्वास भी व्याप्त है जिससे मुक्त होना कठिन है। स्वामी जी ने विभिन्न स्थानों पर आश्रमों की स्थापना कर जनजातीय लोगों को धर्म व जीवनतत्व के आलोक से आलोकित किया। जब तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया इस नृशंस हत्या के पीछे माओवादियों के हाथ होने की बात को बार–बार उछाल रहा था तब समाज ने इसे स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार किया लेकिन शंका जाहिर की यह हो सकता है कि मतांतरण कार्य में भारी पैसे खर्च करने वाले संगठनों द्वारा माओवादियों को प्रचुर धन देकर हत्या करवायी गई हो ।

अखबार ने इन संगठनों तथा माओवादियों के बीच संबंधों की जांच की मांग भी की। समाज ने लिखा– इस वीभत्स घटना के पीछे माओवादियों के हाथ होने की बात कह कर इस कार्य को अंजाम देने वाले अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस मामले में माओवादियों के शामिल होने का दावा किया जाता है तो अपने हित की पूर्ति के लिए प्रचुर धनराशि दे कर इन्हें इस्तेमाल किया गया है,यह मानना पडेगा। इन संगठनों की गतिविधि तथा माओवादियों के साथ इनके संबंधों की जांच होनी चाहिए। कंधमाल जिले के वनवासी इलाकों में स्वामी जी द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा प्रकल्पों का क्या होगा, उनमें पढ रहे वनवासी बालक–बालिकाओं का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया को कोई चिंता नहीं थी । लेकिन इसके विपरीत जमीन से जुडी हुई मीडिया को इस बात की चिंता थी। केवल इतना ही नहीं समाचार पत्र ने इस हत्या के पीछे के गहरे षडयंत्र का भी पर्दाफाश किया। समाचार पत्र ने लिखा कि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के साथ ही उनकी दो अगली पीढियों के उत्तराधिकारियों की भी हत्या कर दी गई है जिससे सदा के लिए वनवासी कल्याण समिति के कार्यक्रम समाप्त हो जायें ।

इसी तरह एक और प्रमुख अखबार धरित्री ने लिखा कि स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या से पूरे देश को विचलित होना चाहिए। यहां पर यह स्वीकार करना पडेगा कि स्वामी जी विदेशी ग्राहम स्टेन्स की तरह गोरे नहीं थे इसलिए राष्ट्रीय मीडिया में उनकी हत्या पर चर्चा नहीं होगी। आस्ट्रेलिया व अमेरिका के भी ईसाई संस्थाओं द्वारा भारत से कूटनीतिक संबंध खत्म करने का दबाव नहीं डाला जाएगा । सोनिया गांधी व उनके सहयोगी ओडिशा के दौरे पर आकर स्वामी जी की हत्या के पीछे की शक्तियों को बेनकाब करने के लिए सहयोग करने संबंधी बयान नहीं देंगे ।

इसी तरह एक और प्रमुख अखबार धरित्री ने लिखा कि स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या से पूरे देश को विचलित होना चाहिए। यहां पर यह स्वीकार करना पडेगा कि स्वामी जी विदेशी ग्राहम स्टेन्स की तरह गोरे नहीं थे इसलिए राष्ट्रीय मीडिया में उनकी हत्या पर चर्चा नहीं होगी। आस्ट्रेलिया व अमेरिका के भी ईसाई संस्थाओं द्वारा भारत से कूटनीतिक संबंध खत्म करने का दबाव नहीं डाला जाएगा । सोनिया गांधी व उनके सहयोगी ओडिशा के दौरे पर आकर स्वामी जी की हत्या के पीछे की शक्तियों को बेनकाब करने के लिए सहयोग करने संबंधी बयान नहीं देंगे ।

केवल इतना ही नहीं तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी उल्टा प्रश्न करेंगे कि मतांतरण होने वाले स्थान पर स्वामी जी आखिर जा क्यों रहे थे? कुछ लोग यहां तक कहेंगे स्वामी जी राजनीति से प्रेरित कार्यों में लिप्त थे। सबसे दुख की बात यह है कि स्वामी जी जैसे सामाजिक परिवर्तन के लिए लडाई लड रहे व्यक्ति की स्मृति को एक दिन के बंद के बाद लोग भूल जायेंगे। अनुगुल जिले में जन्मे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती ने कंधमाल जिले में अपने संग्राम को क्यों कई दशकों तक जारी रखा इसे भविष्य की पीढी नहीं जान पाएगी । आल इंडिया कैथोलिक यूनियन के अध्यक्ष तथा आल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के महासचिव जान दयाल, फिल्म निर्माता महेश भट्ट तथा जमायते–उलेमा–ए–हिन्द के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से मिला और उन्हे एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में इस हत्या का दोश प्रशासन के ही सिर मढते हुए कहा गया कि यदि प्रशासन ने स्वामी लक्ष्मणानंद के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अगर उन्हें पहले ही जेल में ठूंस दिया होता तो हत्या की नौबत नहीं आती। स्वामी जी के लिये चर्च और उसके समर्थकों के मन में कितना जहर भरा था यह इस ज्ञापन की भाषा से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यह भाशा राष्ट्रीय मीडिया को आपत्तिजनक नहीं लगती।

भारत का राष्ट्रीय मीडिया इस पूरे प्रकरण में पार्टी बना नजर आता है जिसके लिये जमीनी हकीकत से अधिक महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मजबूरी समझ में आती है। उन्होंने अपना दामन जिन वैश्विक ताकतों के साथ बांधा हुआ है उसमें वे शर्मिन्दगी जाहिर करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि वह भी सच से आंखें चुराये । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देकर लोगों के शयन कक्षों में झांकने की कोशिश करने वाले जुझारू संवाददाता आखिर ऐसे मामलों में तह तक क्यों नहीं जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि संपादक के स्तर पर यह क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता कि उसका अखबार पूरी स्थानीय मीडिया से नितांत भिन्न समाचार क्यों छाप रहा है। राष्ट्रीय मीडिया जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा, लोगों का विश्वास बनाये रखने में सफल नहीं हो सकेगा। ■

..... academic and professional functions at the right level. It is also a fact that all of these approvals are based on the reports of the 'visiting committees of experts' appointed by the regulatory bodies! They are all academics, mostly from peer institutions committed to save quality in higher education!

Needless to reiterate, conditions are indeed very complex and no linear solutions appear in sight. However one may be avers to refer to it, the issue is that of rampant corruption and erosion of professional values, a phenomenon visible all around. The major complaint against most of the ill-functioning institutions has been lack of adequate infrastructure and non-availability of qualified staff. It applies equally well to a college of teacher preparation, a medical or a dental college or a management institution. It is not confined to private sector alone. A case in point is that of the state government of Madhya Pradesh. For over three decades, not a single recruitment on regular basis has been made in the postgraduate colleges of education which are supposed to train good quality teachers. 'Teachers' on deputation from government schools are managing these colleges. For bureaucracy, there is no difference between a teacher and a teacher educator! Governments change but no one cares to recognize the role of teacher educators in the context of quality. The conditions may not be very different in other institutions as well. Most of the IIT' IIM's and central universities are suffering acutely from the shortage of academic faculty. Roughly it could be around 25% in many cases.

Facing this acute shortage of academic faculty, central institutions are under orders to increase seats consequent to 27% reservations. Even if it gets spread over three years, one can rest assured that institutions shall function under acute shortage of academic and infrastructure support. Recently, the central government has again asked the central institutions to put up their demands for financial resources once again. The final figure invariably decided upon by the Babus of the ministry. Then there are installment, utilization certificates, objections, visits to Delhi and all that you know. Money flow to institutions from the central government is a treacherous process.

While the entire academic community is deeply concerned on this undue haste and lack of understanding of the nuances of institution building, another shocking development is taking place simultaneously. The new IIT's and IIM's which are to function from this year, shall be the responsibility existing IIT's! In Rajasthan even the location is not finally decided but IIT Kanpur will admit candidates for it and 'teach' them. Thus not only IIT Kanpur but others as well shall handle additional seats for reservations and full first year admission of a new IIT! If this is not killing quality and eroding brand names what else it could be? One wonders why well established and fully ' autonomous' IITs, with global reputation succumb to orders that are academically and professionally unacceptable? How can private institutions be asked to follow norms and standards if this is the example being set up before them by the central government?

(Professor J.S. Rajput is the former Chairperson of the National Council for Teacher Education (NCTE). He was the Director of the National Council of Educational Research and Training (NCERT) during 1999-2004.) ■

CRUSADE FOR SURVIVAL

Udalguri, Darang (Asom)

- Ashish Bhave -

The Bodo villages were attacked by Bangladeshi Muslims on 3rd Oct. 2008, just after Ramjan and Eid which affected Bodo, Assamese, Bihari, Santhali, Garo, Bengali and Nepali peoples. 96000 of those affected people are now in 50 relief camps of Udalguri and Darrang districts.

The growing Bangladeshi infiltration was opposed in Arunachal Pradesh a few months ago and they were driven out from the state. After this, different Student Organizations of Assam took the drive of detection of Bangladeshis in Assam in t July and August. It was opposed by the Muslim Organizations and aa Assam bandh was called on by AMSU (Assam Minority Students' Union) 13th August and on 14th August by MUSA (Muslim Students' Union of Assam). But it was ineffective and opposed by the people in Udalguri district. In a pre planned retaliation, Muslims attacked Hindu shopkeepers with arms.

The Muslims planned to attack the Bodos after the Eid which was revealed by some Assamese Muslims of Udalguri district to the Bodos and Assamese on their contact. Accordingly they were also mentally prepared to face the attack. The Hindu and Christian villages were attacked on 2nd October night to 4th Oct night, burned and looted. The Muslims were in thousands and with arms and sophisticated weapons as well.They attacked Sonaripara, Kuptimari and Jhargaon villages on 3rd Oct. night, which were totally burnt down and an old woman

named Keteri Boro of Jhargaon aged 75 year was burnt alive. They faced a good reply from the police personnel who were posted there who fought for four hours and fired 197 rounds of bullets to save their own lives. The attackers, who had sophisticated weapons with them, were shouting 'Allah Ho Akabar', 'Age Barho', 'Ghar Khali Karo— Ham Jalayega' and they hoisted Pakistani flags at 2 places there.

The peoples in different relief camps said that Muslims were with arms, shouting 'Allah Ho Akbar', 'Pakistan Zindabad' and hoisted Pakistani flags. But it was denied by the Govt. of Assam and said it was their religious flag.

In support of the above, 'Pakistani Daily' wrote on 8th Oct'08 with the heading **'Pakistani Flag is a symbol of Freedom in India'**.The news read as follows:-

"Depressed from how New Delhi is suppressing local Assamese people who want to carve a separate home land out of India, people in Assam waved Pakistan's flags in five districts. The Eastern Indian state is one of the dozen Indian states in the North and East where ferocious freedom movements are in full swing, demanding the right of self determination from Indian rule....."

23 non Muslims died and 43 injured till 6th Oct 2008. At present there are 96,090 peoples from 321 villages took shelter in 50 relief camps (Muslims camps not included).

It was observed that Muslims are getting support from the administration while the non Muslims are put under Curfew and their movements are being restricted. It was reported by the camp inmates that the Muslim extremists are moving openly with sophisticated arms. Some of the examples of govt. supports to the Muslims can be sited as follows-

1. On 14th August 2008, Sri Dipak Rabha was killed at Bhalukmari chowk in front of Dr. Saddiq Ali Ahmed, S.D.P.O.of Udalguri.
2. On 4th Oct.2008, Sri Francis Sangma (45), Sri Patros Marak (40) and Sri Naren Marak (44) from village Borduaneza were killed by Muslims in the presence of Mohd. Imdadul Hussain, S.P.
3. When the Muslims were burning the houses of Hindus and Christians, the police remain silent, but when it was retaliated they were checked by the police.

People lost their faith on administration and preparing for their own safeguard. Youths are working hard to guard their respective villages and crops day and night. Total 22 villages were burnt yet.

Different social organizations and students' bodies are highly active in helping the victims in relief camps by providing food and clothes. The organizations active in the relief work are All Bodo Students' Union (ABSU), All Assam Students' Union (AASU), All Assam Gorkha Students' Union, Bodo Sahitya Sabha, All BTAD Bengali Yuva Chhatra Federation etc. Kalyan Ashram has started its Medical services through a mobile medical van and preparing for other relief materials. The National Democratic Front of Bodoland (NDFB) which is in cease fire now has also provided relief materials.

Muslims used bow and arrows during their attacks on Hindus. It was made of Santhali design. It was reported that muslims compelled some of the Santhali villages to help them during their attacks for which the women and children of Santhalis were made captive. The Santhali Youths were also found collecting relief materials from their own villages for relief camps. It is a fact that even 3000 Santhals are also in relief camps along with the Bodos and other communities.

Smt. Khauni Daimari, an old lady from Khaouklachuba village reported at Mudaiguri H.S. relief camp that their temple of Bathou was damaged by Muslims and Pakistani Flag was hoisted. At Kharupetia town (Darrang dist.) the Durga idol was damaged and cow blood was poured on its mouth and shouted- *"Kya Shakti hai is me?"*

Sri Sansuma Khungur Bwisumatary (M.P., Kokrajhar LS) in his speech at Mudaiguri H.S. relief camp on 7th Oct.2008 said, "Flag of Pakistan on the Indian soil is a great threat to the unity and integrity of India. It is an act of Muslim Fundamentalist and Jihadis. It is our land and it must remain ours for which we have to fight tooth and nail." ■

परिचर्चा

परमाणु करार मुद्दे पर अमेरिका ने भारत को गुमराह किया हैं ?

अवधेश कुमार मलिक

करार के नाम पर हो रहे षडयंत्र को समझने के लिए कुछ और बातों को समझना बहूत जरूरी है। इस करार को लेकर जब आखिरी दौर की बात चीत चल रही थी और इसका मसौदा अमेरिकी सीनेट में था, उस समय वहां एक घटना घटी, जिसके अन्तर्गत अमेरिकी पैनल के एक प्रभावशाली पैनल ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी जिसमें अमेरिकी कानून के उल्लंघन करने की हालत में भारत को किसी भी एनएसजी देशों या फिर अन्य किसी श्रोत से परमाणु उपकरण सामग्रियों या प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को रोकने का प्रावधान है। अमेरिका इस समझौते से यही चाहता है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के अन्य भागीदार देशों या किसी अन्य श्रोतों से परमाणु उपकरण सामग्री या फिर प्रौद्योगिकी भारत के हाथ ना लग जाए। क्या अमेरिका की यह साफ सी चाल भारत की मनमोहन–सोनिया सरकार नहीं समझ पा रही है।

सुनील

मनमोहन सिंह लाख इस बात की दुहाई दें कि भारत पर हाइड एक्ट लागू नहीं होगा लेकिन अमेरिका ने बड़ी चालाकी के साथ अपने तमाम नीतियों के जरिए हाइड एक्ट को ही मजबूत बनाया है। बहूत साफ–साफ शब्दों मे विधेयक में लिख दिया गया है कि 123 समझौते का हर एक प्रावधान हाइड एक्ट या परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की कानूनी आवश्कताओं के अधीन रहेगा। भारतीय सत्ताधीशों के दावे की पोल राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के उस बयान से भी खुल जाती है, जिसमें वे कहते हैं कि 123 समझौता एक राजनीतिक वचनबद्धता है, जिससे आवश्कता पड़ी तो वे मुकर भी सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ बातें हैं। मसलन इस समझौते के बाद भारत परमाणु ईंधन की रिप्रोसेसिंग उस समय कर पाएगा जब वह अमेरिका द्वारा किए गए समझौते और अमेरिकी दिशा निर्देश का ठीक–ठीक पालन करेगा।

परवेश

एक बात जो इस समझौते की भाषा से संबंधित है मेरी समझ में नहीं आ रही है कि समझौते में निगरानी करने वालों के लिए इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक की जगह एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? इसका साफ सा मतलब यही है कि हम समझौते में अपनी परमाणु शक्ति तक विदेशियों का पहुंचना समझौते के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार इस विषय में देश की आम जनता को भटकाने का प्रयास कर रही है।

मोहित कंसल

परमाणु करार के मसले पर जिस प्रकार सरकार ने विश्वास मत पाने को ही सेंस ऑफ द हाउस मानकर इसे आगे बढ़ाकर लोकतांत्रितक प्रक्रिया की अनदेखी करने का ही काम किया है। अब लोकतांत्रिक तरीके से किए गए विरोध को महत्व नहीं मिलता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यदि सही मायने में किसी समूह को अपना विरोध दर्ज कराना है तो उसे विरोध के नए रास्ते तलाशने होंगे। ऐसे समय कानून और लोकतांत्रिक मर्यादा की बात करना बेमानी प्रतित होता है। ■

मालेगांव बम विस्फोट प्रकरण

इस विषय पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' द्वारा परिचर्चा आयोजित है। अधिक से अधिक 500 शब्दों में अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखकर या टाइप कराकर पासपोर्ट आकार के अपने एक चित्र के साथ 15 अगस्त तक प्रेषित करें।

सम्पादक, 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति
136, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली–110001

Himachal Pradesh

ABVP Win HPU Students Council Elections

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) swept elections to the HPU student council body winning four of the five seats that were under contest and conceded only one to rival Students Federation of India.

Vivek Dogra from the university law school won as secretary while Anupma Guleria from Mandi College won the position of Joint-secretary. Both belong to ABVP.Of the three executive committee seats contested, Manuj Tehran of MCM DAV College Kangra and Nishant Sharma of Government College Chamba, who were backed by ABVP won. Sachin Kumar of Sanjuli Government College was the lone SFI winner on the students council.

The students council elections are being held after a long gap and all colleges affiliated to the university participate in the mandate handed out. Vivek Dogra said, "Since the past six years, the students have not been able to put forth their ideas. Now that we have a voice, issues relating to students would be taken up on priority."

Uttaranchal

Another sweep in Dehradun

ABVP swept the polls for Students' Union held in DAV (PG) College. ABVP won the major posts of President and University Representative. ABVP presidential candidate Shri Rahul Rawat got 2644 votes and defeated NSUI candidate by a margin of 856 votes. Sumit Pundir of ABVP got 2311 votes and defeated NSUI candidate Shivesh Bahuguna (1671 votes) for the post of University Representative.

Delhi

ABVP activists try to burn Hasan's effigy, detained

Jamia Millia University (JMI) vice-chancellor Mushirul Hasan led a rally condemning terror attacks and demanding judicial probe into the Jamia Nagar encounter. Things reached a flashpoint when 25 members of ABVP came to the area to protest against Hasan decision to provide legal aid to the arrested students.

Though the march ended at 11.30 am and the gathering dispersed, things nearly took an ugly turn when ABVP activists came face to face with locals of Jamia Nagar. Although the official release of the university stated that the protesting students entered the campus shouting slogans against the vice-chancellor, eyewitnesses said the students were stopped by locals outside the campus. The ABVP activists also tried to burn the effigy of Hasan when they were stopped by the police and were taken into custody. They were later released.

In a statement ABVP said,"It is wrong on the part of the university and MHRD to allow use of university resources for terrorists. We were protesting peacefully when local residents roughed us up in front of the main gate of the university."

Madhya Bharat

ABVP demands VC's dismissal for forgery

ABVP demanded Bhoj Open University's Vice-Chancellor Kamlakar Singh's immediate dismissal for his alleged copying of PhD thesis.

"The vice chancellor should tender his res-

ignation owning moral responsibility. If he fails to do so, the governor should dismiss him for this criminal act," ABVP's Zonal Organisational Secretary Vishnudutt Sharma said while talking to reporters here.

He said it was inexplicable why Madhya Pradesh Governor Balram Jakhar failed to act against the VC despite a forgery case was lodged against the latter. But hoped that good sense would prevail and the Governor, who is also the chancellor, should dismiss Kamlakar from his post.

"Such incident set a bad precedent in the educational circle of not only Madhya Pradesh, but also across the country," Sharma said. He said that this was a first instant in the country that a such serious case is levelled against a vice-chancellor.

Alleging that the government machinery was involved in the case, he said if Singh was not sacked the ABVP would launch state-wide agitation. ABVP registered an FIR against the VC recently, police added.

Rajasthan

ABVP launches tirade against Bangladeshis

ABVP has started mobilising people by organising a students' rally against the Bangladeshi immigrants.

The ABVP activists, holding placards and banners, took to the streets. They shouted slogans to voice their resentment over the large number of illegal Bangladeshis who are staying in India.The rally was addressed by ABVP Zonal Organising Secretary Shri Sunil Bansal. He claimed that there are two lakh Bangladeshi refugees living in several slums in Jaipur posing a danger to the national security. "These immigrants are utilizing our resources like power, water, land and above all hitting our economy by making our youths jobless," he said.

He said ABVP has identified illegal slums like Bagrana, Jyotinahar and right below the nose of state assembly, Aamrod-ka-bagh, of becoming a hub of Bangladeshi immigrants. He claimed that the series of blasts that rocked Jaipur on May 13 is the handiwork of organisations operating from Bangladesh.

ABVP has asked the government to identify them and deport them before polls. "Many of them enjoy the status of being Indian nationals after being issued with ration cards and identity cards. They make a living by serving as mechanics, rickshaw pullers, labourers and other petty jobs," said Umakant Bhardwaj, State Secretary, ABVP.

Bihar

ABVP Activists Force Colleges to Close Down

Hundreds of activists of ABVP in Patna on Wednesday took part in the nationwide drive against massive influx of illegal immigrants from Bangladesh while accusing the Congress-led UPA government of ignoring the issue for political gains

The protestors, going from college to college in Patna including Patna Law College, Patna Science College, Patna College, Vanijya Mahavidyalaya, Darbhanga House, B. N. College, Magadh Mahila College, JD Women's College etc, forced the cancellation of the classes despite security arrangements at many colleges

The UPA government at the Center is deliberately choosing to look the other way as millions of Bangladeshis, many with ties to terrorist organizations, are crossing the border and entering India causing disturbances in many states including Assam, Tripura, and West Bengal, said Rajesh Sinha, an ABVP leader.

Jharkhand

ABVP College Bandh Successful

Classes in colleges, schools and an university across the state were disrupted today, as members of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) registered their protests against infiltrators from Bangladesh into India.

The protests were a part of a nationwide bandh called by ABVP.

In Ranchi, activists took to the street and forced schools and colleges to shut gates for the day. Members, carrying posters stating "Detect, delete and deport" visited colleges.

In Jamshedpur, a group of 100 ABVP activists visited various colleges and campaigned against illegal infiltrators.

"Bangladeshi infiltrators have become a part of the population, illegally. We want to make students aware of the phenomenon so that they, too, can protest against the infiltrators. We want students' support in our fight," said Amitabh Senapati of ABVP. The bandh passed off peacefully in Dumka. All schools, including private ones, and colleges remained closed for the day. Sidho Kanhu Murmu University remained paralysed.

ABVP activists took out a rally at Pakur, where demonstrations against illegal migrants have became common. In Dhanbad, colleges and schools remained closed due.

Maharashtra

43rd State Conference

Protesting against intrusion of five crore Bangladeshi in the country, which become a national-strait, ABVP has decided to launch a nation-wide agitation from December 17.

Rajan Welukar, vice-chancellor of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University released a book "Bangladeshi-Ghuskhori" after inaugurating 43rd State Conference of ABVP.

Milind Marathe, National vice-president of ABVP while addressing the first session of state conference said that as per government's figures it was stated that there are 5 crore Bangleshi-intruder and central government is not seen serious on the issue.

He said that ABVP is running on a democratic basis and fighting against Naxalism and terrorism but Congress, communists are trying to malign our image for politics, he added.

ABVP national, state-level office-bearers and activists from different parts of the state were participated in the convention.

Karnataka

National Seminar on Bangladeshi Infiltration

Taking serious note of the menace of Bangladeshi infiltrators in India, former Inspector General of Police, Arunachal Pradesh, R K Ohri opined that the problem of illegal immigration has been ignored for decades due to the minority centric selfish political designs.

Speaking at a national seminar on 'Bangla infiltration' organised by the ABVP at Bharatiya Vidya Bhavan in Bangalore, Ohri lamented that Bangla infiltration could be a turning point in the history of India.

"The north-eastern region will be the first victim of this 'tectonic tsunami,' the reverberations of which are now being felt all over the country," he added. "The most alarming fact is that over three-and- a-half crore Bangladeshi infiltrators have entered our country during the last three decades," Ohri observed.

WOSY Deewali Milan Programme - Bangalore

WOSY Deewali Milan Programme - Pune

Vidyarthi Chetana Yathra - Jammu

Seminar at Kota - Rajasthan

44th State Conference - Madhya Bharat

देशव्यापी बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आन्दोलन

चलो चिकन नेक

छात्रों की विशाल रैली

एवं

प्रदर्शन

17 दिसम्बर 2008

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्

ABVP